

जमीन का फर्जी एग्रीमेंट बनवाकर 78.97 लाख की ढगी करने वाला पकड़ाया

एसईसीएल का सेवानिवृत्त कर्मचारी हुआ था ठगी का शिकार

छ.ग.फ्रंटलाइन अम्बिकापुर। जमीन का फर्जी एग्रीमेंट दस्तावेज भू-स्वामी के जानकारी में दिए बिना तैयार करवाने और 78 लाख 97 हजार रुपये की ठगी करने के मामले में लंबे समय से फरार आरोपी को गांधीनगर थाना एवं साइबर सेल अम्बिकापुर की संयुक्त टीम ने घेराबंदी करके गिरफ्तार किया।



जो दत्ता कॉलोनी अम्बिकापुर में रहता है। निकुंज उक्त महिला को रॉयल पार्क कॉलोनी के पीछे ले गया और करीब पौने दस डिसमिल जमीन दिखाकर उक्त जमीन अनिल अग्रवाल का होना बताया। साथ ही कहा कि भूमि स्वामी अनिल की बहन को कैसर हो गया है, उसके इलाज के लिए वह जमीन बेच रहा है। इसके बाद उक्त जमीन का एग्रीमेंट अपने नाम से कराकर रखने की बात कहा और विश्वास दिलाया कि

वह जमीन का सीधे रजिस्ट्री करा देगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद जमीन बिक्री हेतु 2,10,000 रुपये प्रति डिसमिल के हिसाब से सौदा तय हुआ और वह अलग-अलग तिथि में एडवांस रकम प्राप्त करके रजिस्ट्री की बात को टालते रहा। मार्च 2019 तक महिला ने निकुंज गुप्ता को कुल 17 लाख 5 हजार रुपये दे दिया। इसके बाद भी रजिस्ट्री नहीं करने पर जब महिला आपत्ति की तो वह भूमि स्वामी की बहन के बहुत ज्यादा सीरियस होने की बात कहकर रजिस्ट्री के लिए टालते रहा। इसके बाद निकुंज गुप्ता महिला को बताया कि टाइम आउट सिनेमा के सामने करीब 2 एकड़ 37 डिसमिल जमीन दो राजवाड़े भाई बेच रहे हैं, और वह जमीन को लेने के लिए

घेराबंदी करके आरोपी तक पहुंची पुलिस

मुखबि से मिली सूचना पर थाना गांधीनगर एवं साइबर सेल अम्बिकापुर की संयुक्त टीम ने घेराबंदी करके रेड कार्रवाई की और आरोपी निकुंज गुप्ता पिता बालकेश्वर गुप्ता 44 वर्ष, निवासी शनि मंदिर के आगे को हिरासत में लिया और पूछताछ की तो उसने महिला को जमीन दिलाने के नाम पर लाखों रुपये की ठगी करना स्वीकार किया। विवेचना में अग्रिम कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार करके पुलिस ने न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। आरोपियों की गिरफ्तारी में थाना प्रभारी गांधीनगर निरीक्षक प्रदीप जायसवाल, उप निरीक्षक नवल किशोर दुबे, साइबर सेल प्रधान आरक्षक भोजराज पासवान, विकास सिन्हा, बंधु सारथी, आरक्षक जितेश साहू, रमेश राजवाड़े, राहुल केरकेट्टा, अमन पुरी, राहुल सिंह, महिला आरक्षक प्रिया रानी, सरस्वती सिंह, मोती केरकेट्टा सक्रिय रहे।

इन्हें राजी कर अलग-अलग तिथि को जमीन का एडवांस रकम किसी ना किसी बहाने प्राप्त करते रहा, और रजिस्ट्री के लिए टालते रहा। निकुंज गुप्ता पिता बालकेश्वर गुप्ता व अन्य के द्वारा जमीन बिक्री करने का झांसा देकर छलपूर्वक 78 लाख

छ.ग.फ्रंटलाइन बलरामपुर। जिले के खड़ियादामर ग्राम पंचायत बचवार की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अंजू यादव ने महिला एवं बाल विकास विभाग की गंभीर लापरवाही और भ्रष्टाचार का खुलासा कर हड़कंप मचा दिया है। विभाग के जिम्मेदार अधिकारी जहां निरीक्षण के नाम पर केवल खानापूर्ति कर रहे हैं, वहीं इसका सीधा खामियाजा मासूम बच्चों को उठाना पड़ रहा है, वे पौष्टिक आहार तक से वंचित हैं। कार्यकर्ता अंजू यादव का कहना है कि रेडी-टू-ईट खाद्य सामग्री कभी भी उनके केंद्र तक नहीं पहुंचा। कई बार सामग्री बिना सूचना के बुद्धूदीह में उतार दिया जाता है, जिसे उन्हें खुद लेबर लगाकर लाना पड़ता है। हैरानी की बात यह है कि सितंबर माह से अब तक रेडी-टू-ईट, सत्तू का एक भी खेप केंद्र में नहीं पहुंचा है। सहायिका नहीं होने के कारण पूरे केंद्र का अकेले संचालन करने वाली कार्यकर्ता ने परियोजना कार्यालय को कई बार शिकायतें दीं, परंतु कोई



दोस कार्रवाई नहीं हुई। सुपरवाइजर पर भी मनमानी और दुर्व्यवहार के गंभीर आरोप उठाने लगाए हैं। अंजू यादव का कहना है कि सुपरवाइजर मीटिंग में उनसे सीधे मुंह बात तक नहीं करती, जिससे कार्य में समन्वय का अभाव बना रहता है।

आंगनवाड़ी भवन का किराया 2 साल से बकाया

कार्यकर्ता अंजू यादव ने कहा कि जहां आंगनवाड़ी संचालित हो रहा है, उस भवन का किराया दो वर्ष से नहीं मिला है। गैस सिलिंडर का पैसा तक नहीं दिया गया। केंद्र में केवल थाली और कड़ाही है, भोजन बनाने के लिए आवश्यक सामग्री तक उपलब्ध नहीं है। ग्रामीणों की नाराजगी सामने आई गांव के लोगों का कहना है कि आंगनवाड़ी केंद्र नियमित नहीं खुलता। यदि बच्चे जाते भी हैं तो उन्हें कोई खाद्यान्न सामग्री नहीं मिलती। ग्रामीणों ने जब इस विषय पर कार्यकर्ता के पति से बात करनी चाही तो उन्हें रायपुर भेजने की धमकी दी गई, जिससे भोले-भाले ग्रामीण भयभीत होकर अपनी बात कहने से कतराते हैं। कुपोषण मुक्त कैसे बनेगा बलरामपुर जिम्मेदार विभागीय अधिकारियों के तुलमुल खवे, निरीक्षण की खुलेआम अनदेखी और आपसी विवादों के कारण बचवार गांव के नन्हे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। सरकार जहां कुपोषण मुक्त दावा करती है, वहीं जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल उलटा दिखाई दे रही है। देखने वाली बात यह होगी कि क्या परियोजना अधिकारी, सुपरवाइजर और संबंधित आंगनवाड़ी स्टाफ कुंभकर्ण नौद से जागेंगे या फिर हमेशा की तरह एक-दूसरे पर दोषारोपण का खेल चलता रहेगा।

राहगीर को ठोकर मारकर भागा एंबुलेंस का चालक छ.ग.फ्रंटलाइन अम्बिकापुर। बलरामपुर जिला के राजपुर थाना अंतर्गत एम्बुलेंस का चालक राहगीर को ठोकर मारकर मौके से फरार हो गया।

ग्राम सेवारी निवासी रामसेवक सिंह पिता स्व. लहरू राम ने राजपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया है कि 10 दिसम्बर, बुधवार को शाम लगभग 6-7 बजे भदार बाजार से उसका पुत्र रवि किशन मरावी 26 वर्ष पैदल घर वापस आ रहा था। ग्राम भदार में बाजार के पास एम्बुलेंस वाहन क्रमांक सीजी 07 सीपी 0541 का चालक चुनवा, सतेन्द्र पिता बुधवा राम, निवासी ग्राम हरदीलोगा सेवारी लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाते हुए उसे ठोकर मारकर मौके से फरार हो गया। भदार निवासी राजा ने इसकी सूचना घायल युवक के पिता को दी। जब वे घटनास्थल पहुंचे तो उनका पुत्र अचेत अवस्था में पड़ा था। राजपुर स्वास्थ्य केंद्र में पुत्र का उपचार कराने के बाद रामसेवक सिंह ने घटना की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई है, जिस पर मामला दर्ज करके पुलिस अग्रिम वैधानिक कार्रवाई कर रही है।

विधायक के कथित फर्जी जाति प्रमाणपत्र विवाद में फिर टली सुनवाई

आदिवासी समाज भड़का, दी अंतिम चेतावनी, एनएच किया जाम

छ.ग.फ्रंटलाइन बलरामपुर। प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र की विधायक शकुंतला सिंह पोते के कथित फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में गुरुवार को प्रस्तावित सुनवाई एक बार फिर आगे बढ़ा दी गई। निर्धारित तारीख पर दोनों पक्षों के अधिवक्ता एवं समाज के प्रमुख कलेक्टर कार्यालय पहुंचे थे। बढ़ते विवाद की आशंका को देखते हुए संयुक्त जिला कार्यालय के 500 मीटर दायरे में धारा 144 लागू कर दिया गया था। पूरे परिसर को बैरिकेड से घेरकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे और भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। मामले की प्रक्रिया आगे बढ़ने के बाद सुनवाई की नई तारीख 29 दिसंबर तय किए जाने से आदिवासी समाज भड़क उठा। समाज के प्रतिनिधियों का कहना था कि तिथि पर तिथि बढ़ाई जा रही है, और सुनवाई पूरी नहीं की जा रही है। यह सिर्फ समय का नुकसान है। निर्धारित सुनवाई नहीं होने से



विधायक के विवादित बयान से समाज में उबाल विधायक शकुंतला सिंह पोते के कथित बयान 'हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार' को लेकर आदिवासी समाज में गहरा आक्रोश है। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि ऐसा शब्द अत्यंत निंदनीय है। समाज के लोगों का कहना है कि यह बात सोशल मीडिया के माध्यम से सामने आई है। इसलिए बड़ी सुनवाई की तारीख पूर्व आयोग अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने गुरुवार को हुई सुनवाई के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि मामले की तारीख 11 दिसंबर निर्धारित थी, जिस पर वे अपने अधिवक्ताओं और दस्तावेजों के साथ उपस्थित हुए। उनके पक्ष द्वारा सभी आवश्यक दस्तावेज छानबीन समिति के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है। बचव पक्ष के अधिवक्ताओं ने जाति प्रमाण पत्र से संबंधित मूल रजिस्टर मंगाने की मांग की, इस पर छानबीन समिति ने दस्तावेज मंगाने अतिरिक्त समय मांगा है। इसी कारण अगली सुनवाई की तारीख बढ़ाकर 29 दिसंबर कर दी गई है। उन्होंने कहा कि हमें पूर्ण भरोसा है निर्णय हमारे पक्ष में ही आएगा, क्योंकि विधायक शकुंतला सिंह पोते के पुस्तैनी दस्तावेज तक उत्तर प्रदेश से मंगवाकर समिति के समक्ष जमा किया गया है।

नाराज समाज के लोग सामाहिक बाजार छोड़कर सीधे कलेक्टर कार्यालय की ओर कूच कर गए। मुख्यालय स्थित शहीद पार्क के पास पहुंचते ही पुलिस ने बैरिकेड लगाकर उन्हें रोक दिया, यहां कुछ देर के लिए पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तनाव की स्थिति रही। अब 29 दिसंबर की नई तारीख पर सभी की निगाहें टिक गई हैं। समाज के प्रतिनिधियों ने अंतिम चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर अगली तारीख पर भी फैसला नहीं हुआ तो जिले में चक्काजाम के साथ अनिश्चित कालीन आंदोलन शुरू किया जाएगा। इस दौरान छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज बलरामपुर के जिला अध्यक्ष बसंत कुजूर, रामदेव जगते, जयश्री, धन सिंह धुर्वे सहित बड़ी संख्या में समाज के लोग उपस्थित हैं

जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे स्कूली बच्चे, बुजुर्ग

सड़क, पुलिया जैसी मूलभूत परेशानियों को सुनने वाला कोई नहीं

छ.ग.फ्रंटलाइन उदयपुर। विकास का दावा करने वाले नेताओं और शासन-प्रशासन के ढोल की पोल विकासखंड से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम पंचायत केशगवां खोल रहा है। आजादी के 78 साल बाद भी ग्राम पंचायत के लालमटिया पारा में सीसी सड़क बनाने के बाद भी पुलिया नहीं बनने से स्कूली बच्चे, बुजुर्ग और माताएं परेशान हैं, और खतरों से भरा सफर करने के लिए बाध्य हैं। स्कूली छात्राओं का कहना है कि नदी पार करने के लिए लकड़ी का सीढ़ीनुमा पुलिया है, जिससे आने-जाने में काफी परेशानी होती है। ग्रामीणों के द्वारा गांव के सचिव, सरपंच और जनप्रतिनिधियों को कई बार इससे अवगत कराया गया लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। पुलिया बनेगा वर्षों से सुनने को मिल रहा है। बता दें कि नदी को पार करने के लिए 15 परिवारों ने लकड़ी से सीढ़ीनुमा पुलिया का निर्माण किया है, जिससे नदी के ऊपर से आवागमन होता है। इससे छोटे बच्चे और परिवार के मजबूत सदस्य किसी तरह पार हो जाते हैं, किंतु बुजुर्ग नदी को पार नहीं कर पाते हैं। ऐसे में वे बुजुर्ग अपने ही मोहल्ले में दूसरे के घर आना-जाना नहीं कर पाते हैं। लालमटिया के किसानों ने बताया कि खुद के कमाई का कुछ सामान बेचना



हो या सोसाइटी जाना हो बुजुर्गों को बमुश्किल सहारा देना पड़ता है। आधा किलोमीटर की दूरी पार करने के बाद ही सड़क तक पहुंचा जा सकता है। राशन लाने-ले जाने में भी उन्हें इस लकड़ी के पुल का सहारा लेना पड़ता है। गांव की लड़कियां पीने का पानी लेने के लिए लकड़ी के पुल के सहारे आना-जाना करती हैं। इस दौरान शरीर का नियंत्रण बिगड़ने का खतरा मंडराते रहता है। नदी में गिरने का जोखिम लिए ये दशकों से आना-जाना कर रहे हैं। मोहल्ले वासियों ने बताया कि बड़े जनसेवकों और पंचायत के प्रतिनिधियों की अनदेखी से ऐसे आलम में उन्हें गुजर-बसर करना पड़ रहा है। इधर गांव के सरपंच और सचिव ग्रामीणों को होने वाली समस्या के प्रति किसी प्रकार का बात करने से बच रहे हैं। ग्रामीणों ने शासन-प्रशासन से तत्काल इस समस्या से निजात दिलाने की मांग की है।

आमजन फोटो खींचकर किए शिकायत, तो संबंधितों के विरुद्ध होगी तत्काल कार्रवाई

एक जनवरी से सभी अधिकारी-कर्मचारियों के लिए आधार-बेसड उपस्थिति अनिवार्य

छ.ग.फ्रंटलाइन अम्बिकापुर। ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले आम नागरिकों की लगातार प्राप्त शिकायतों को देखते हुए प्रशासन ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। अक्सर यह शिकायत मिलती थी कि नागरिकों के कार्यालय पहुंचने पर अधिकारी-कर्मचारी समय पर मौजूद नहीं रहते या अपने निर्धारित कक्ष/शाखा में उपलब्ध नहीं होते, जिससे ग्रामीणों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इस समस्या के समाधान के लिए कलेक्टर ने कार्यालयों में अनुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु कड़े निर्देश जारी किए हैं। जिले के सभी विभागों और कार्यालयों में कार्यरत प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी की उपस्थिति अब आधार-बेसड सिस्टम से दर्ज होगी। इसी उपस्थिति के आधार पर वेतन आहरण किया जाएगा। सभी कर्मचारियों को एक जनवरी से पूर्व अनिवार्य रूप से आधार आधारित पंजीयन पूरा करना होगा। पंजीयन में समस्या होने पर

निर्धारित किए गए कार्यालय से सहयोग लेने कहा गया है। सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 5.30 बजे तक अपने कक्ष, शाखा, सीट में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहना होगा। यदि कोई अधिकारी, कर्मचारी अनुपस्थित पाया जाता है और आमजन इसकी फोटो सहित शिकायत प्रस्तुत करते हैं, तो संबंधित के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई की जाएगी। दौरे की जानकारी दर्ज करना अनिवार्य-यदि कर्मचारी या अधिकारी शासकीय कार्य से अन्य कार्यालय या दौरे पर जाते हैं, तो इसके लिए कार्यालय में एक पंजी संघारित किया जाएगा, जिसमें जाने का उद्देश्य, स्थान और समय का उल्लेख आवश्यक होगा। मोबाइल नंबर होंगे सार्वजनिक-कार्यालयों में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सभी कर्मचारियों एवं अधिकारियों का मोबाइल नंबर कार्यालय के सूचना पटल पर प्रदर्शित किया जाएगा। प्रत्येक टेबल पर नाम, पदनाम और मोबाइल नंबर की नेम

प्लेट अनिवार्य रूप से रखी जाएगी। नियमित उपस्थिति जांच-कार्यालय प्रमुख प्रत्येक दो दिन में अपने कार्यालय की उपस्थिति जांच करेंगे। समय पर उपस्थित न रहने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। आकस्मिक निरीक्षण में नियमों का पालन न होने पर संबंधित कार्यालय प्रमुख भी जिम्मेदार होंगे। अनुविभाग एवं ब्लॉक कार्यालयों में भी कड़ाई-जिले के सभी विभागीय और विकासखंड स्तरीय कार्यालयों में इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं। कलेक्टर विलास भोसकर ने स्पष्ट किया है कि इन निर्देशों का उद्देश्य आम जनता को समय पर सेवा उपलब्ध कराना, कार्यालयों की कार्यप्रणाली को सुचारू बनाना और ग्रामीण नागरिकों को अनावश्यक परेशानी से बचाना है। सभी विभागों को इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

सरगुजा में हाईब्रिड नेशनल लोक अदालत का आयोजन कल

छ.ग.फ्रंटलाइन अम्बिकापुर। राष्ट्र विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के निर्देशानुसार, 13 दिसंबर, शनिवार को सरगुजा जिले में हाईब्रिड नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सरगुजा अम्बिकापुर के.एल. चरयाणी के मार्गदर्शन में जिले के सभी न्यायालयों में होगा, जिसमें व्यवहार न्यायालय सीतापुर भी शामिल है। लोक अदालत में मामलों का निपटारा आपसी सहमति (राजीनामा) के आधार पर किया जाएगा। इसके लिए न्यायालयों में अलग-अलग खण्डपीठों का गठन कर दिया गया है। इन खण्डपीठों में निम्न प्रकार के मामले राजीनामा शोध दाण्डिक प्रकरण, व्यवहार संबंधी प्रकरण चेक बाउंस के मामले, पारिवारिक विवाद, सड़क दुर्घटना दावा प्रकरण, श्रमिक/मजदूर संबंधी विवाद,

भूमि अधिग्रहण प्रकरण, राजस्व संबंधी मामले, विद्युत चोरी से जुड़े प्रकरण तथा प्री-लिटिगेशन का समाधान किया जा सकेगा। लोक अदालत की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि पक्षकार न्यायालय में उपस्थित होकर या वक्तुअल वीडियो

कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में आए बिना भी अपने मामलों का निपटारा कर सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए आवश्यक लिंक प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय सरगुजा की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा। जिला एवं सत्र

न्यायाधीश के.एल. चरयाणी ने जिले के आम नागरिकों से अपील की है, वे हाईब्रिड नेशनल लोक अदालत का लाभ उठाएं और आपसी सहमति से अपने विवादों का त्वरित समाधान कर समाज में सौहार्द और शांति स्थापित करें।

Lakshmi Narayan Hospital
HEALING MATTER



डॉ. गौरव कुमार
एम.बी.बी.एस., डीएनबी (ओपी)
पूर्व एमएसिड स्पेशलिस्ट (टाटा मेन हॉस्पिटल)
हड्डि एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ



डॉ. आयुषी अग्रवाल
एम.बी.बी.एस. (ऑनर्स) गोल्ड मेडल,
एमएस (गोल्ड मेडल), डीएनबी
स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ

लक्ष्मी नारायण अस्पताल
समय: प्रतिदिन सुबह 11:00 बजे से 05:00 बजे तक
9 गवर्नी चौक, संगम गली, अम्बिकापुर (छ.ग.) ☎ 8305960517, 8251071106, 07774-356715

कलेक्टर ने धान खरीदी केन्द्र बड़कीमहरी एवं पस्ता का किया निरीक्षण

बलरामपुर, छ.ग. फ्रंटलाइन। जिले में धान खरीदी के कार्य को सुचारू रूप से संपन्न कराने तथा धान की अवैध खरीदी एवं बिक्री को रोकथाम सुनिश्चित करने हेतु कलेक्टर श्री राजेन्द्र कटारा के द्वारा धान खरीदी केन्द्रों का सघन दौरा कर समुचित व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया और सुचारू धान खरीदी के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

कलेक्टर श्री राजेन्द्र कटारा ने विकासखण्ड बलरामपुर के धान खरीदी केन्द्र बड़कीमहरी एवं पस्ता धान खरीदी केन्द्र का आकस्मिक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने धान खरीदी पंजी, निरीक्षण पंजी एवं बारदाना पंजी का अवलोकन करते हुए अब तक हुए धान के भण्डारण, कुल उठाव के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने धान तौलाई, धान के रख-रखाव की जानकारी समिति प्रबंधक से लेते हुए आवश्यक निर्देश दिए। कलेक्टर ने धान के गुणवत्ता का भी अवलोकन किया तथा धान की नमी का भौतिक सत्यापन कराकर जांच की।

इस दौरान कलेक्टर श्री कटारा ने धान खरीदी केन्द्रों में उपस्थित किसानों से चर्चा करते हुए धान खरीदी केन्द्र के व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने किसानों को साफ-सुथरे एवं गुणवत्तायुक्त धान, खरीदी केन्द्र में बिक्री हेतु लाने की समझाईश दी जिससे धान खरीदी प्रक्रिया में किसी प्रकार

की बाधा ना आए। उन्होंने समिति प्रबंधक से धान की समुचित जाँच के उपरांत ही गुणवत्तायुक्त एवं साफ-सुथरे धान की खरीदी करने के निर्देश

प्रकार की बाधा नहीं आयी। वे कहते हैं कि पहले हमें धान विक्रय करने में समय लगता था। लेकिन अब समय पर तौलाई, बारदाना उपलब्ध होने

में 15829.20, डीपाडीह में 6114.80, डोंगरो में 6482.40, गांजर में 5042.80, त्रिकुण्डा में 14707.60, बगरा में 9234, तातापानी में 12024.40,

धंधापुर में 13653.60, डौरा में 8235.20, पस्ता में 5794.40, बड़कागांव में 17614, बरतीकला में 13137.60, बरदर में 9867.20, आरा में 3824, बरियों में 14405.20, बलंगी में 10030.40, बलरामपुर में 14174, बसंतपुर में 15132, धुलसीकला में 3358.80, भंवरमाल में 20689.60, रामानुजगंज में 11792.40, महाराजगंज में 19269.60, महावीरगंज में 9812, विजयनगर में 17068, रघुनाथनगर में 10706.40, रनहत में 7174.80, राजपुर में 18197.60, दोलंगी 8318.80, रामचन्द्रपुर में 5218.80, रामनगर में 14138, वाडफनगर में 8002.80, स्याही में 9779.20, विरेन्द्रनगर में 18377.60, सरना में 11546.40, सेवारी में 11484.80 एवं सामरी में 2234.80 क्विंटल धान किसानों से खरीदी की गयी है।

से किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आई। जिससे अनावश्यक प्रतीक्षा और भीड़ से राहत मिली। धान खरीदी केन्द्र में तौला, भंडारण और पावती सहित संपूर्ण प्रक्रिया तेज, व्यवस्थित और पारदर्शी ढंग से संचालित हो रही है। इससे किसानों में सरकार के प्रति भरोसा और संतोष बढ़ा है। श्री विमल तिग्गा बताते हैं कि उनके पास 3 एकड़ की जमीन है, इस वर्ष उन्होंने अपने लगान और मेहनत से उपज में बढ़ोतरी की है। वे बताते हैं कि इस वर्ष 149 बोरी धान का विक्रय किया है और समर्थन मूल्य पर खरीदी पश्चात मिलने वाली राशि से अपने घर और आगामी फसल के बनाई गई कार्ययोजना अनुसार मक़े की फसल में उपयोग करेंगे।

जिले के धान उपार्जन केन्द्रों में 522902 क्विंटल धान की खरीदी राज्य शासन द्वारा समर्थन मूल्य

की जा रही है। किसानों से धान की खरीदी करने के लिए 49 सहकारी समितियों के अंतर्गत 49 धान उपार्जन में अब तक कुल 522902 क्विंटल धान की खरीदी की गई है। साथ ही 840 क्विंटल धान मीलिंग हेतु राईस मिलरों द्वारा उठाव कर लिया गया है। कलेक्टर के निर्देशानुसार अवैध धान पर लगातार कार्यवाही भी की जा रही है।

जिले के सहकारी समिति कपिलदेवपुर में 6907.20 क्विंटल धान की खरीदी की गई है। इसी प्रकार बादा में 5381.20, कुसमी में 7926, जवाहरनगर में 4411.20, कामेश्वरनगर में 23752, कोदवा 2612, गोपालपुर में 7148.80, भंडरी 4830.40, चांदी में 16878.80, जमड़ी में 22145.20, जिगड़ी में 4372.40, जोकापाट (भरतपुर) में 1960.80, डूमरपान में 12102.80, डिण्डो

शासकीय महाविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस पर व्याख्यान

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

बिश्रामपुर। शासकीय महाविद्यालय विश्रामपुर में अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस पर व्याख्यान कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती एवं छत्तीसगढ़ महतारी के छायाचित्र पर दीप प्रज्वलन तथा राजकीय गीत के साथ हुआ। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में संजय गुप्ता सदस्य अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार अपराध नियंत्रण छत्तीसगढ़, सत्यनारायण जायसवाल पूर्व जिला पंचायत सदस्य तथा सामाजिक कार्यकर्ता संतोष द्विवेदी मुख्य रूप से उपस्थित रहे।

सामाजिक कार्यकर्ता संतोष द्विवेदी ने मानव जीवन में अधिकारों के महत्व पर विद्यार्थियों को सरल भाषा में जानकारी दी। पूर्व जिला पंचायत सदस्य सत्यनारायण जायसवाल ने मानव अधिकारों का संक्षिप्त विश्लेषण करते हुए कहा कि धरती पर सभी मानव का समान

अधिकार है और कर्तव्यों का पालन करते हुए जीवन जीना ही वास्तविक मानवता है। उन्होंने घोषणा किया कि 90 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्र-

सहायता के लिए वे सदैव तैयार रहेंगे। इस अवसर पर विद्यार्थियों को डायरी और पेन भी वितरित किए गए। महाविद्यालय के प्राचार्य डीपी



छात्राओं को उनकी ओर से 5100 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। मुख्य वक्ता संजय गुप्ता ने मानव अधिकारों की विस्तृत व्याख्या करते हुए कहा कि कमजोर और जरूरतमंद वर्ग की सहायता करना हर मानव का दायित्व है। उन्होंने घोषणा किया कि निर्धन विद्यार्थियों की

कोरी ने विद्यार्थियों से कहा कि अधिकारों की प्राप्ति के साथ-साथ कर्तव्यों के प्रति सजग रहना भी आवश्यक है। कार्यक्रम में अतिथियों को स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र भेंट किए गए। कार्यक्रम का संचालन एवं आभार प्रदर्शन अतिथि व्याख्याता अंकुश सिंह सिसोदिया ने किया।

सेजेस जयनगर में बच्चों को दी गई मृदा स्वास्थ्य कार्ड पर जानकारी

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

बिश्रामपुर। मृदा संरक्षण कार्यक्रम के अवसर पर आज स्वायत्त हेल्थ योजनातर्गत पीएम श्री सेजेस जयनगर में मृदा स्वास्थ्य कार्ड के संबंध

विविध सूचक पोषक तत्व का मिट्टी से संबंध को वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी श्री अशोक सोनवानी द्वारा व्यापक रूप से विद्यार्थियों के बीच जानकारी दिया गया। इस दौरान विद्यार्थी सोखने को उत्सुक नजर आए मिट्टी नमूना लेने की वैज्ञानिक तरीकों को प्रैक्टिकल रूप में वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी ब्लॉक टेक्नोलॉजी श्रीमती पायल गिरी एवं रवींद्र व्यास, पंकज बेक द्वारा समझाया गया एवं ऑनलाइन करने की विधि को बताया गया। प्रशिक्षण को सफल बनाने में विद्यालय के विद्यार्थियों के अलावा विद्यालय की प्राचार्य पुष्पा राय, पूर्व प्राचार्य वीरेंद्र जायसवाल एवं सभी शिक्षक मौजूद थे।

मिट्टी नमूना एकत्र करने के बारे में बताया गया मिट्टी की उपयोगिता संरक्षण उत्पादक तथा

शिक्षक मौजूद थे।

कलेक्टर के आदेश के बाद भी सरकारी जमीन पर कायम अतिक्रमण

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

बिश्रामपुर। सरकारी जमीन को लेकर एक बार फिर विवाद गहरा गया है। युवा कांग्रेस भटगांव विधानसभा अध्यक्ष विकी समद्वार ने कलेक्टर सुरजपुर को शिकायत पत्र सौंपकर आरोप लगाया है कि राजस्व न्यायालय के आदेश के बावजूद आज तक सरकारी भूमि से अतिक्रमण नहीं हटाया गया, जिससे प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर प्रश्नचिह्न लग रहे हैं। युका नेता विकी समद्वार ने बताया कि मामला खसरा नंबर 191 की शासकीय भूमि से संबंधित है, जिस पर दिनेशचंद्र मंडल, तिलकचंद्र मंडल और विकी चंद्र मंडल द्वारा कथित रूप से अवैध

कब्जा किया गया है। इस संबंध में कलेक्टर द्वारा 7 अक्टूबर 2025 को तहसीलदार लटोरी



को तत्काल अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया गया था। लेकिन शिकायतकर्ता के अनुसार दो महीने का समय

बीत जाने के बाद भी किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है। विकी समद्वार ने जापान में उल्लेख किया है कि कलेक्टर के लिखित आदेश के बावजूद राजस्व अमला कार्रवाई नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि कलेक्टर द्वारा दिए गए आदेश का पालन न होना, राजस्व न्यायालय के आदेश की अवमानना के समान है। प्रशासनिक निष्क्रियता जनता के बीच गलत संदेश दे रही है। समद्वार ने कलेक्टर से तत्काल संज्ञान लेकर अतिक्रमण को हटवाने तथा आदेश की अवहेलना करने वाले अधिकारियों पर आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की है।

जिला स्तरीय करियर काउंसिलिंग शिविर आज

बलरामपुर, छ.ग. फ्रंटलाइन। जिला प्रशासन बलरामपुर-रामानुजगंज द्वारा विद्यार्थियों के शैक्षणिक उन्मुखीकरण एवं भविष्य निर्माण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मोटिवेशनल सेमिनार एवं कैरियर मार्गदर्शन कार्यशाला का आयोजन 12 दिसंबर शुक्रवार को काका लरंगसाय स्टेडियम, शंकरगढ़ में किया जाएगा। कार्यक्रम चैंपियन ऑफ चेंज पहल के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है, जिसका लक्ष्य जिले के विद्यार्थियों में आत्मविश्वास, सकारात्मक सोच और लक्ष्य-निर्धारण की क्षमता विकसित करना है। जिसमें मोटिवेशनल स्पीकर प्रिंस वर्मा विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे।

एसआईआर अभियान का कलेक्टर ने किया अवलोकन

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

बिश्रामपुर। गलियों में घूमता रहा, घर-घर दस्तावेजों की जांच पड़ताल करता रहा। ज्ञात हो कि नगर पंचायत विश्रामपुर का गठन 6 मार्च 2003 को हुआ था। अवलोकन किया गया। गौरतलब है कि बुधवार को कलेक्टर एस. जयवर्धन के नेतृत्व में राजस्व, एसईसीएल प्रबंधन व नगरीय प्रशासन की बड़ी टीम ने विश्रामपुर के वे दो बूथ क्रमांक 94 और 98 का निरीक्षण किया, जहां 50 प्रतिशत से भी कम एसआईआर फॉर्म जमा हुए थे। कलेक्टर के साथ संयुक्त कलेक्टर पुष्पेंद्र शर्मा, एसडीएम शिवानी जायसवाल, सुरजपुर तहसीलदार सूर्यकांत साय, पिलखा नायब तहसीलदार मीना सिंह, क्षेत्रीय महाप्रबंधक डॉ. संजय सिंह, क्षेत्रीय सुरक्षा अधिकारी अमरेंद्र नारायण सिंह, नप सीएमओ सुशील कुमार तिवारी, नप उपाध्यक्ष दीपेंद्र सिंह चौहान, राजस्व निरीक्षक, पटवारी और बीएलओ भी मौके पर मौजूद रहे। यह पूरा दल

राज्यों में जा चुके हैं, कई छांटर वर्षों से खाली पड़े मिले और सबसे चौकाने वाली बात यह है कि कुछ घर ऐसे जहां पूरा परिवार कागजों में मतदाता है,



आज वोटर लिस्ट में 9730 मतदाताओं के नाम दर्ज हैं। लेकिन जब अधिकारियों ने जमीनी सत्यापन शुरू किया, तो जो स्थिति सामने आई वह साधारण नहीं थी। एसआईआर में यह तथ्य सामने आया है कि कई मतदाता वर्षों पहले रिटायर होकर गांव लौट चुके हैं, कई मृत व्यक्तियों के नाम अब भी सूची में मौजूद हैं, सैकड़ों परिवार स्थायी रूप से दूसरे जिलों,

और प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर बड़ा असर पड़ेगा स्थानीय लोगों में इस आशंका ने हलचल मचा दी है। कलेक्टर एस. जयवर्धन ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि हर छांटर का भौतिक सत्यापन अनिवार्य, मृत व्यक्तियों व बाहर जा चुके लोगों के नाम तत्काल हटाए और बीएलओ की लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची सिर्फ कागजी औपचारिकता नहीं, बल्कि स्थानीय शासन की रीढ़ है। इसका शुद्धिकरण आवश्यक है। विशेष सत्यापन अभियान ने यह स्पष्ट कर दिया है कि विश्रामपुर नगर पंचायत अपनी वास्तविक जनसंख्या के आधार पर संकट की स्थिति में खड़ी है। यदि भविष्य में मतदाताओं की वास्तविक संख्या और कम निकलती है, तो यह नगर प्रशासनिक बदलावों की बड़ी प्रक्रिया से गुजर सकता है। फिलहाल पूरे क्षेत्र को निगहें इस अभियान की अगली रिपोर्ट पर टिकी हुई हैं।

पर वास्तविकता में वहां कोई नहीं रहता है। मतदाताओं की तेजी से घटती वास्तविक संख्या ने प्रशासन की भी विचलित किया है। नगरीय निकायों की मान्यता जनसंख्या और मतदाता संख्या पर आधारित होती है। ऐसे में यदि वास्तविक मतदाता संख्या 50 प्रतिशत से नीचे चली जाती है, तो नगर पंचायत का दर्जा वापस लिया जा सकता है, इससे विकास योजनाओं, बजट

उत्तरप्रदेश से लाया जा रहा 600 बोरी अवैध धान सहित ट्रक वाहन जब्त

बलरामपुर, छ.ग. फ्रंटलाइन। शासन के निर्देशानुसार खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए



अलसुबह तहसील वाडफनगर अंतर्गत उत्तरप्रदेश राज्य से 1 ट्रक वाहन में अवैध धान परिवहन कर लाया जा रहा था। वाहन क्रमांक सीजी 15 डीजे 7293 ट्रक से लगभग 600 बोरी अवैध धान को जब्त कर चौकी वाडफनगर को सुपुर्द किया गया है। ज्ञातव्य है कि धान खरीदी की प्रक्रिया सुचारू रूप जारी है। साथ ही कलेक्टर श्री राजेन्द्र कटारा के निर्देशन में अवैध परिवहन एवं संग्रहण पर लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व वाडफनगर श्री नीरनिधि नंदेहा के मार्गदर्शन में राजस्व एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम के द्वारा

मिली मार्गदर्शन, गतिविधियों और व्यावहारिक प्रशिक्षण ने सभी शिक्षकों में नई ऊर्जा भर दी है। प्रशिक्षण प्रमाणपत्र प्राप्त करते हुए शिक्षकों ने कहा कि यह अनुभव उनके शिक्षण कार्य को और अधिक प्रभावी, तकनीक आधारित तथा विद्यार्थियों के लिए लाभकारी बनाएगा। इस महत्वपूर्ण आयोजन में पीएमश्री राज्य प्रभारी आशीष गौतम, सुब्बा नायडू, दिनेश चतुर्वेदी, संदीप, मुस्कान अग्रवाल, कल्पना दास, लोकनाथ, अमित, शीतल, लोमेश सिन्हा, श्वेता सहित अन्य शिक्षकों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। प्रशिक्षण के साथ यह अपेक्षा जताई जा रही है कि आने वाले समय में पीएमश्री स्कूलों की कक्षाएं और भी आधुनिक, आकर्षक और सीखने-सिखाने की नई मिसाल पेश करेंगी।

एसआईआर को लेकर एसडीएम ने की समीक्षा बैठक

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

बिश्रामपुर। एसआईआर की तिथि बढ़ने उपरांत आज एसडीएम शिवानी जायसवाल की उपस्थिति में समीक्षा बैठक आहूत की गई। बैठक में एसडीएम शिवानी जायसवाल ने कहा कि ग्राउंड स्तर पर एसआईआर का सत्यापन कार्य की स्थिति कैसी है, इसका सभी बीएलओ व बीएलए की उपस्थिति में समीक्षा की गई। यहां पर समीक्षा के दौरान यह बात सामने आई कि बूथ क्रमांक 98 व 100 में कार्य कुछ हद तक अधूरा है। जिस पर एसडीएम ने कहा कि सभी आपसी तालमेल के साथ उक्त दोनों बूथ की एसआईआर प्रक्रिया को पूरी तरह पूर्ण करें। बैठक में एसडीएम ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया में जो लोग भी अनुपस्थित हैं, उनसे फोन के माध्यम से भी संपर्क करके यदि अपना फॉर्म जमा करना चाहते हैं तो उनके फॉर्म को भरवाकर पूर्ण कराया जाए। यहां पर एसडीएम सूची की विवेकपूर्ण को पूर्ण रूप से सुधारने की बात कही गई। एसडीएम शिवानी जायसवाल ने बताया कि एसआईआर की सूची को सभी बीएलओ व बीएलए के समक्ष रखा गया, जिसमें कुछ पाषण्डों द्वारा और लोगों के नाम को जुड़वाने हेतु पहल करने का आश्वासन दिया गया है। इस दौरान सुरजपुर तहसीलदार सूर्यकांत साय, नगर पंचायत विश्रामपुर उपाध्यक्ष दीपेंद्र सिंह चौहान, पाषण्ड रविशंकर बडवा, संजित यादव, पटवारी अरुण जायसवाल, नप के रनदीप दास व अन्य उपस्थित थे।

आईआईटी जम्मू में छत्तीसगढ़ के 151 विज्ञान शिक्षकों का हुआ प्रशिक्षण

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

बिश्रामपुर। छत्तीसगढ़ के पीएमश्री स्कूलों को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी-2020 की दिशा में और अधिक सशक्त बनाने तथा शिक्षकों को आधुनिक तकनीक में दक्ष करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग एवं समग्र शिक्षा छत्तीसगढ़ शासन के निर्देश पर राज्यभर के 151 विज्ञान एवं गणित शिक्षकों ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जम्मू में पांच दिवसीय विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किया। इस प्रशिक्षण का नेतृत्व पीएमश्री राज्य प्रभारी आशीष गौतम द्वारा किया गया।

ज्ञात हो कि भारत सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना पीएमश्री स्कूल देश में गुणवत्तापूर्ण और समान शिक्षा की नई पहल मानी जा रही है। स्मार्ट क्लास, डिजिटल लर्निंग,

अत्याधुनिक लैब्स, ग्रीन स्कूल, कौशल एवं खेल शिक्षा जैसी सुविधाओं से लैस ये स्कूल अन्य शैक्षणिक संस्थानों के लिए रोल मॉडल बनाए जा रहे



हैं। इसी श्रृंखला में अध्यापन कर रहे शिक्षकों का कौशल विकास अत्यंत आवश्यक माना गया, जिसके लिए यह प्रशिक्षण आयोजित किया गया। पांच दिवसीय कार्यशाला में शिक्षकों को स्मार्ट लैब मैनेजमेंट, 3 डी प्रिंटर संचालन, साइबर

सिक्वोरिटी, गूगल क्लासरूम, ड्रोन टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आधारित बेहतर कक्षा संचालन, तथा आईआईटी की उन्नत लैब्स का अवलोकन कराया गया। शिक्षकों ने प्रयोगात्मक गतिविधियों के माध्यम से तकनीक को महसूस किया, जिससे भविष्य की कक्षाएं अधिक इंटरैक्टिव, नवाचारपूर्ण और प्रायोगिक होंगी। बताया जा रहा है कि सरगुजा संभाग के 20 पीएमश्री स्कूलों सहित सुरजपुर, जयनगर, बतरा, प्रेमनगर, कोतवा, शिवप्रसादनगर, जशपुर के चयनित शिक्षक प्रशिक्षण हेतु पहुंचे थे। इनमें जयनगर से व्याख्याता खुबचंद राजवाड़े, शिक्षक मुस्कान अग्रवाल, विशाल शर्मा, हिमांशु शर्मा, नैन्सी तिकी, अर्चना ठाकुर, लोमेश सिन्हा, रविंद्र कुमार भगत शामिल रहे। कार्यशाला में

सिक्वोरिटी, गूगल क्लासरूम, ड्रोन टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आधारित बेहतर कक्षा संचालन, तथा आईआईटी की उन्नत लैब्स का अवलोकन कराया गया। शिक्षकों ने प्रयोगात्मक गतिविधियों के माध्यम से तकनीक को महसूस किया, जिससे भविष्य की कक्षाएं अधिक इंटरैक्टिव, नवाचारपूर्ण और प्रायोगिक होंगी। बताया जा रहा है कि सरगुजा संभाग के 20 पीएमश्री स्कूलों सहित सुरजपुर, जयनगर, बतरा, प्रेमनगर, कोतवा, शिवप्रसादनगर, जशपुर के चयनित शिक्षक प्रशिक्षण हेतु पहुंचे थे। इनमें जयनगर से व्याख्याता खुबचंद राजवाड़े, शिक्षक मुस्कान अग्रवाल, विशाल शर्मा, हिमांशु शर्मा, नैन्सी तिकी, अर्चना ठाकुर, लोमेश सिन्हा, रविंद्र कुमार भगत शामिल रहे। कार्यशाला में

1977 का निर्णायक मोड़: जब सरगुजा ने इतिहास बदला

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

अम्बिकापुर। 1975-77 के आपातकाल ने भारत की राजनीतिक संवेदना को झकझोर दिया था। इस कठोरतम दौर में पूरे देश में जनमत करवट ले रहा था, लोकतंत्र की पुनर्स्थापना और जनता की आवाज को वापसी एक राष्ट्रीय आंदोलन बन चुकी थी। इसी उफनते समय में लरंग साय दोबारा चुनाव मैदान में उतरे। 1977 का चुनाव केवल एक चुनाव नहीं था, वह भारतीय राजनीति के इतिहास की सबसे बड़ी जनभावनात्मक लहर थी और उसके हृदय में सरगुजा भी धड़क रहा था।

लरंग साय की ऐतिहासिक विजय- एक राजनीतिक मिथक का अंत

सरगुजा में वर्षों से यह मान्यता थी कि राजपरिवार का समर्थन ही चुनावी सफलता की चाबी है। कई राजनीतिक अध्ययनों में यह कहा जाता था कि

राजमहल की इच्छा जनमत की दिशाह्व पर 1977 ने यह मिथक पहली बार तोड़ा। लरंग साय की जीत ने स्पष्ट कर दिया कि जब जनता जागती है, तो सत्ता को परंपराएँ भी बदल जाती हैं। उनकी जीत केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं थी, वह सामाजिक एवं राजनीतिक जागरण की घोषणा थी।

काका लरंग साय की आवाज गुँजती क्यों थी?

क्योंकि वह केवल नेता नहीं थे वह सरगुजा की मिट्टी, संस्कृति और जनभाषा के प्रतीक थे। उनकी वाणी में पहाड़ों की साफ हवा थी। उनके स्वर में खेतों की धड़कन थी, और सबसे महत्वपूर्ण वे दिल्ली में भी गर्व से कहते थे: हम सरगुजिहा हन। हनुमन् साहस ने जनता को भरोसा दिया कि यह नेता हमारा है। हमारी भाषा, हमारी संस्कृति और हमारी पीढ़ी का सच्चा प्रतिनिधि। 1977 का यह मोड़ न केवल लरंग



साय का उदय था, बल्कि सरगुजा की राजनीतिक आत्मनिर्भरता का जन्म भी था।

1977 से 1999: विश्वास, संघर्ष और विकास का 22 वर्षों का सफर भारतीय जनता पार्टी ने लगातार 22 वर्षों तक लरंग साय पर अपना विश्वास बनाए रखा। राजनीति में

इतना दीर्घ विश्वास यह केवल दल की निष्ठा नहीं, बल्कि नेता की ईमानदारी, संगठनात्मक क्षमता और जनसमर्थन का प्रमाण है। लोकसभा में तीन बार सरगुजा की आवाज बनें थें काका लरंग साय। तीन बार संसद पहुँचकर लरंग साय ने जनप्रतिनिधित्व को औपचारिकता नहीं रहने दिया। उन्होंने मुद्दों को राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा बनाया। सरगुजा की पहाड़ी सड़कों को राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने के प्रस्ताव लोकसभा के पटल पर रखा। तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के नए संस्थानों की आधारशिला, आदिवासी विकास योजनाओं के लिए पृथक बजट और नीति-निर्माण, रेलवे लाइनों का विस्तार और अम्बिकापुर को राष्ट्रीय नेटवर्क में जोड़ने की माँग, वनाधिकार, खनन नीति और विस्थापन जैसे प्रश्नों

को जोरदार ढंग से उठाना जैसे उठाना आदि। वे उन दुर्लभ सांसदों में थे जिनकी फाइलें सिर्फ चलती नहीं थीं, उनकी आवाज के साथ आगे बढ़ती थीं।

क्यों कहा गया सरगुजा का विकास पुरुष

क्योंकि उन्होंने विकास को केवल योजनाओं तक सीमित नहीं रखा। उनकी राजनीति का केंद्र सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रेलवे और जनपहचान था। उनकी वजह से ही सरगुजा पहली बार राष्ट्रीय राजनीति के मानचित्र पर स्पष्ट दिखाई देने लगा। और यही कारण है कि जनता ने उन्हें केवल नेता नहीं माना, बल्कि सरगुजा की आत्मा का प्रतिनिधि माना। भारतीय जनता पार्टी के लोग ही नहीं बल्कि विपक्षी दलों के लोग भी लरंग साय का नाम लेकर कहते हैं कि अब लरंग साय जैसा नेता पैदा नहीं होगा।

अग्निवीर प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थियों की सूची जमा करने निर्देश, सीईओ ने युवाओं से की अपील

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

भैयाथान। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र सूरजपुर ने ग्रामीण युवाओं के लिए महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। केंद्र द्वारा जनपद पंचायतों को पत्र भेजकर अग्निवीर भर्ती प्रशिक्षण के लिए चयनित एवं इच्छुक अभ्यर्थियों की जानकारी तत्काल उपलब्ध कराने को कहा गया है, ताकि प्रशिक्षण प्रक्रिया समय पर संचालित हो सके। पत्र के अनुसार जनपद पंचायत मुख्यालयों में निर्धारित स्थान पर अग्निवीर भर्ती के लिए शारीरिक प्रशिक्षण संचालित किया जा रहा है। प्रशिक्षण का लाभ अधिक से अधिक युवाओं को मिल सके, इसके लिए जनपद पंचायतों को



निर्देशित किया गया है कि एक सप्ताह के भीतर पत्र अभ्यर्थियों की सूची प्रस्तुत की जाए। इसी क्रम में जनपद पंचायत भैयाथान के सीईओ विनय गुप्ता ने क्षेत्र के युवाओं से अपील की है कि जो भी युवा अग्निवीर प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं

झीगादोहर में वाटरशेड महोत्सव 2025 सम्पन्न

जल संरक्षण, विकास कार्यों का लोकार्पण और हितग्राही लाभ वितरण के साथ ग्रामीणों में जागरूकता बढ़ी

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

जरही। कृषि विभाग जिला सूरजपुर द्वारा संचालित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (जलग्रहण विकास घटक 2.0) के तहत ग्राम पंचायत झीगादोहर में वाटरशेड महोत्सव 2025 का आयोजन दो दिवसीय कार्यक्रम के रूप में किया गया। इसकी शुरुआत 9 दिसंबर को ग्राम पंचायत करसु स्कूल से प्रभात फेरी, ड्राइंग प्रतियोगिता और जागरूकता गतिविधियों के साथ हुई, जिसमें विद्यार्थियों ने बड़-चढ़कर हिस्सा लिया। श्यामनगर स्कूल में भी इसी प्रकार के कार्यक्रम आयोजित हुए। मुख्य कार्यक्रम 10 दिसंबर को झीगादोहर में आयोजित हुआ,



जिसमें मुख्य अतिथि विधायक प्रतापपुर शकुंतला पोर्ते तथा अध्यक्षता जिला पंचायत अध्यक्ष चंद्रमणी पैकरा ने की। सरस्वती वंदना के बाद 3 निर्माण कार्यों का लोकार्पण और 4 कार्यों का भूमिपूजन किया गया। ग्रामीणों के बीच रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन कर प्रथम व द्वितीय

पुरस्कार वितरित किए गए तथा वाटरशेड महोत्सव के स्मृति चिन्ह के रूप में मोमेंटो दिए गए। हितग्राहियों को 1 नग मिनी राइस मिल और 2 नग मिनी फ्लोर मिल प्रदान की गई, साथ ही 25-25 हजार की डीबीटी राशि हेतु चेक भी वितरित किए गए। कार्यक्रम में जल संरक्षण के महत्व पर विस्तृत

जानकारी देते हुए जल है तो जीवन है हक की थीम पर लोगों को जागरूक किया गया तथा जनभागीदारी कप 2025 में शामिल होने हेतु प्रेरित किया गया। कार्यक्रम में रेखा राजवाड़े, लवकेश पैकरा, अनुज कुमार राजवाड़े, कुलेश्वरी कुरें, सुखमनिया आथाम, पूनम सिंह, प्रेमवती पटेल, मुकेश सिंह सहित कई जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता और ग्रामीण उपस्थित रहे। इस आयोजन से किसानों को वर्षभर सिंचाई जल उपलब्ध होने, फसल उत्पादन बढ़ाने और कृषि को अधिक लाभकारी बनाने की उम्मीद है। कार्यक्रम में ग्रामीणों के साथ स्व-सहायता समूह की महिलाओं की भी सक्रिय भागीदारी रही।

मानवाधिकार दिवस पर नारी निकेतन ने दिव्यांग युवती को मिलाया अपने परिवार से

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

अम्बिकापुर। नारी निकेतन अम्बिकापुर ने मानवता और सेवा की मिसाल पेश करते हुए पिछले 4-5 वर्षों से लापता मानसिक रूप से विक्षिप्त एवं शारीरिक रूप से विकलांग युवती ममता उर्फ अंशु पासवान को उसके परिवार से मिलाया। यह मिलन विशेष रूप से भावुक रहा क्योंकि मानवाधिकार दिवस के अवसर पर ममता को अपने जीवन का सबसे बड़ा अधिकार घर और परिवार का स्नेह वापस मिला। अक्टूबर 2025 में बैकुंठपुर रेलवे स्टेशन के पास भटकती हुई अवस्था में मिली ममता की मानसिक स्थिति



ठीक नहीं थी और शारीरिक विकलांगता के कारण वह चलने-फिरने में भी असमर्थ थी। 15 अक्टूबर 2025 से वह नारी निकेतन में रह रही थी, जहाँ वह अपना नाम, घर और पहचान तक बताने में असमर्थ थी। नारी निकेतन ने उसे न केवल सुरक्षित आश्रय दिया, बल्कि जिला चिकित्सालय अम्बिकापुर के

मनोरोग विभाग से निरंतर उपचार और संस्था के परामर्शदाताओं द्वारा नियमित काउंसलिंग की सुविधा प्रदान की। धीरे-धीरे मानसिक स्थिति सुधरने पर ममता को अपने पिता का मोबाइल नंबर वापस आया, जिससे उसकी पहचान का महत्वपूर्ण सुरण मिला। संस्था द्वारा संपर्क किए जाने पर पता चला कि ममता नालंदा

(बिहार) की निवासी है। इसके बाद सखी वन स्टॉप सेंटर नालंदा ने फोटो के माध्यम से पहचान की पुष्टि की और उसके परिवार का पता निर्धारित किया। दोनों संस्थाओं के लगातार समन्वय एवं प्रयासों से युवती का पुनर्वास संभव हो सका। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर 2025 को नारी निकेतन में औपचारिक रूप से ममता को उसके पिता कैलाश पासवान और परिजनों को सौंप दिया गया। वर्षों बाद अपनी बेटी को देखकर पिता भावुक हो उठे और संस्था द्वारा की गई देखभाल, सुरक्षा, पोषण, उपचार और सहयोग के लिए गहरी कृतज्ञता व्यक्त की।

विधायक के आतिथ्य में सोनगरा में साइकिल वितरण समारोह धूमधाम से संपन्न

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

जरही। भाजपा मंडल जरही के ग्राम सोनगरा में बुधवार को आयोजित साइकिल वितरण समारोह बेहद उत्साहपूर्ण माहौल के बीच सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि प्रतापपुर विधायक शकुंतला सिंह पोर्ते रहीं, जिनका ग्रामीणों, जनप्रतिनिधियों और विद्यालय प्रबंधन ने गर्मजोशी से स्वागत किया। विद्यालय परिसर अभिभावकों और विद्यार्थियों की उपस्थिति से खासकर भरा रहा। समारोह की शुरुआत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सोनगरा के प्रांगण में हुई, जहाँ विद्यार्थियों ने स्वागत नृत्य और पारंपरिक लोकनृत्य की मनमोहक प्रस्तुतियाँ दीं। बच्चों की प्रतिभा ने कार्यक्रम को जीवंतता और



सांस्कृतिक रंगों से भर दिया। अतिथियों ने बच्चों के आत्मविश्वास और कला की मुक्त कंठ से सराहना की। समारोह को संवोधित करते हुए विधायक शकुंतला सिंह पोर्ते ने शिक्षा, सुरक्षा, छात्रवृत्ति तथा महिला सशक्तिकरण से जुड़ी विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा हमारा प्रयास है

कि किसी भी बच्चे की शिक्षा दूरी या आर्थिक स्थिति के कारण बाधित न हो। बेटियों की शिक्षा और सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। विधायक ने बालिकाओं को उच्च शिक्षा, खेल और प्रतियोगी परीक्षाओं में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के महत्व पर विस्तार से चर्चा की।

छात्राओं को मिली साइकिल, बढ़ी नियमितता की उम्मीद

कार्यक्रम के मुख्य चरण में विधायक पोर्ते ने छात्राओं को साइकिल वितरित की। वे बोलों साइकिल मिलने से बच्चों का विद्यालय आने-जाने का सफर आसान और सुरक्षित होगा। इससे उनकी नियमितता बढ़ेगी और पढ़ाई पर सीधा सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने अभिभावकों व शिक्षकों से विद्यार्थियों को संस्कार, अनुशासन और खेलकूद की दिशा में भी मार्गदर्शन देने की अपील की।

ग्रामीणों ने सराहा पहल, बच्चों में खुशी की लहर

जैसे ही छात्राओं ने साइकिल प्राप्त की, उनके चेहरों पर खुशी और उत्साह छलक उठा।

अभिभावकों ने इस पहल को सराहते हुए कहा कि साइकिल मिलने से बच्चों का लंबा पैदल सफर अब सहज हो जाएगा और समय की बचत से उनके अध्ययन में लाभ मिलेगा। विद्यालय परिसर में पूरे कार्यक्रम के दौरान सकारात्मक ऊर्जा और उत्सव जैसा माहौल बना रहा। विधायक शकुंतला सिंह पोर्ते, सरपंच कृष्णा सिंह, मंडल अध्यक्ष मुकेश सिंह, मंडल उपाध्यक्ष शरद चंद्र द्विवेदी, मंडल महामंत्री दीपक मिश्रा, दशरथ सिंह, समय लाल मिश्रा, जय बहादुर सिंह, मीना श्रीवास्तव, किरण गुप्ता, जिला सोशल मीडिया प्रभारी भाजयुमो राजू शर्मा, अशोक प्रजापति, रामदुलार सिंह, संजय मिश्रा सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, शिक्षक एवं ग्रामीण मौजूद रहे।

किसान शिवनारायण सिंह ने किसान तुंहर टोकन ऐप से घर बैठे काटा अपना टोकन

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

अम्बिकापुर। जिले में धान उपार्जन केन्द्रों में पारदर्शिता, सुगमता और डिजिटल सुविधाओं के कारण किसानों के लिए धान विक्रय प्रक्रिया पहले से अधिक सरल और सहज हो गई है। अम्बिकापुर ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत लिबरा के रहने वाले किसान शिवनारायण सिंह ने धान खरीदी प्रक्रिया पर अपनी संतुष्टि व्यक्त करते हुए बताया कि अब धान बेचने की प्रक्रिया सरल, सहज और पूरी तरह पारदर्शी हो गई है। किसान शिवनारायण सिंह ने बताया कि उनके पास कुल 57.20 किंवटल धान का रकबा है। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपना टोकन घर बैठे किसान तुंहर टोकन ऐप के माध्यम से काटा। टोकन



कटाने में उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हुई। उन्होंने बताया कि दरिमा धान उपार्जन केन्द्र पहुंचते ही समिति कर्मचारियों का पूरा सहयोग मिला। नमी परीक्षण के बाद उन्हें तत्काल बारदाना उपलब्ध कराया गया। किसान ने खुशी व्यक्त करते हुए बताया कि केन्द्र में धान की तौल पूरी तरह पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हुई। श्री शिवनारायण ने कहा है कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के शासन में किसानों को

3100 रुपए प्रति किंवटल धान का मूल्य मिल रहा है, उन्होंने बताया कि सर्वाधिक मूल्य मिलने से किसानों को आर्थिक स्थिति मजबूती हो रही है और वे खेती-किसानी को और बढ़ा पा रहे हैं। धान विक्रय से प्राप्त राशि का उपयोग वे कृषि को सशक्त बनाने में कर रहे हैं। किसान शिवनारायण ने धान व्यवस्था पर संतुष्टि प्रकट करते हुए मुख्यमंत्री और शासन-प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया। जिला प्रशासन द्वारा धान उपार्जन केन्द्रों पर किसानों की सुविधा, सहयोग और पारदर्शिता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है, जिससे धान विक्रय करने वाले किसानों को अब सहज, सरल और सुगम व्यवस्था का लाभ मिल रहा है।

274 हितग्राहियों को डबरी निर्माण की मिली स्वीकृति, जल संरक्षण के साथ आजीविका के मिलेंगे अवसर

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

अम्बिकापुर। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत जिले में आजीविका के अवसर बढ़ाने तथा जल संरक्षण के कार्यों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वाटरशेड के अनुसार जीआईएस एवं क्लॉट एप का उपयोग कर उपयुक्त स्थल पर कार्य को चिन्हित कर आजीविका डबरी निर्माण कार्यों की स्वीकृति की जा रही है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी विनय अग्रवाल ने बताया कि जल संरक्षण एवं जल संवर्धन को प्रोत्साहित करने के लिए जिले में बड़े पैमाने पर आजीविका डबरियों का निर्माण किया जा रहा है। इन डबरियों का उद्देश्य केवल जल संचयन तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके



माध्यम से ग्रामीण परिवारों की बहुआयामी आजीविका सुनिश्चित करना भी है। डबरी निर्माण से हितग्राही मछली पालन तथा सिंचाई सुविधा का लाभ लेकर अपनी आजीविका को बढ़ा रहे हैं। सीईओ श्री अग्रवाल ने बताया कि जिले में वर्तमान में 274 हितग्राहियों को डबरी निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें अम्बिकापुर में 36,

लखनपुर में 27, बतौली में 31, उदयपुर में 45, मैनापट में 50, सीतापुर में 63, लंड्रा में 22 डबरी निर्माण के कार्य की स्वीकृति प्राप्त है। अधिकांश स्थानों पर कार्य प्रारंभ हो गए हैं, इसके अतिरिक्त योजना अंतर्गत बोल्टर चेक डेम, नवीन आंगनबाड़ी भवन, नवीन तालाब निर्माण, तालाब गहरीकरण कार्य प्रमुखता से किए जा रहे हैं।

कलेक्टर ने किया धान खरीदी व्यवस्था का किया औचक निरीक्षण, किसानों से लिया फीडबैक

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

अम्बिकापुर। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के अंतर्गत जिले में धान खरीदी व्यवस्था को सुगम और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से कलेक्टर विलास भोसकर ने आज विभिन्न धान उपार्जन केन्द्रों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने खरीदी व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लेते हुए किसानों से सीधे संवाद कर धान खरीदी व्यवस्था की जानकारी ली। कलेक्टर श्री भोसकर सबसे पहले करजी धान उपार्जन केन्द्र पहुंचे, जहाँ उन्होंने पंजीकृत किसानों की संख्या, अब तक हुई खरीदी, पिछले वर्ष के विक्रय आंकड़े, डीईओ कटिंग, उठाव की स्थिति, मजदूरों का भुगतान, बारदाना एवं तिरपाल जैसी व्यवस्थाओं की



विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने किसान फूल साय से चर्चा कर धान विक्रय प्रक्रिया और उसकी पारदर्शिता पर फीडबैक लिया। किसान ने धान खरीदी व्यवस्था पर अपनी संतुष्टि जाहिर की। इसके बाद कलेक्टर ने दरिमा धान उपार्जन केन्द्र का निरीक्षण किया। जहाँ उन्होंने धान खरीदी, डीईओ कटिंग, उठाव और माइक्रो एटीएम की सुविधा का अवलोकन

किया। इस के दौरान उन्होंने द्विदकालो के किसान अशोक कुमार सिंह से चर्चा की, किसान ने बताया कि उन्होंने घर बैठे ह्यकिसान तुंहर टोकन ऐप के माध्यम से अपना टोकन प्राप्त किया था। केन्द्र पहुंचते ही उन्हें बारदाना उपलब्ध हो गया और बिना किसी परेशानी के धान विक्रय सम्पन्न हुआ। किसान अशोक ने कलेक्टर समक्ष माइक्रो

एटीएम से राशि भी निकाली। इस पर कलेक्टर ने समिति प्रबंधक को निर्देश दिए कि माइक्रो एटीएम के उपयोग का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, जिससे किसानों को बैंक जाने की आवश्यकता कम पड़े। कलेक्टर ने नवानगर और करं धान उपार्जन केन्द्रों का भी निरीक्षण कर खरीद एवं उठाव की स्थिति जानी। उन्होंने पंजीकृत किसानों की संख्या, अब तक हुई खरीदी, डीईओ कटिंग, उठाव, कैरी फॉरवर्ड किसानों, नवीन पंजीयन, रकबा समर्पण, बारदाना उपलब्धता तथा माइक्रो एटीएम सुविधा की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने पोड़ी कला के एक किसान से भी सीधे कर उनका टोकन देखा और धान खरीदी व्यवस्था पर प्रतिक्रिया ली, कलेक्टर ने किसान का बैंक

पासबुक में नियमित रूप से डेट्रो कराने की सलाह दी। कलेक्टर श्री भोसकर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि धान खरीदी प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की लापरवाही न हो, किसानों को समय पर बारदाना उपलब्ध कराया जाए, डीईओ और उठाव का कार्य निर्धारित समयसीमा में पूरा करें, भुगतान में किसी भी प्रकार का विलंब न हो, किसानों के लिए माइक्रो एटीएम की सुविधा प्रभावी रूप से संचालित रहे तथा सभी समितियों में पारदर्शिता और अनुशासन पूर्ण रूप से सुनिश्चित किया जाए। इस दौरान जिला खाद्य अधिकारी वीएस कामटे, सीसीबी नोडल अधिकारी पीसी गुप्ता, डीएमओ अरुण विश्वकर्मा सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।

सम्पादकीय

अब चावल के बहाने नए टैरिफ की तैयारी में ट्रंप

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब चावल के बहाने भारत पर नया टैरिफ थोपने की तैयारी में हैं। हालांकि अभी यह तय नहीं है कि कितना टैरिफ लगाया जा सकता है। उनके इस कदम से लगता है कि वे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे से बोखलाए हुए हैं। इसलिए उन्होंने भारत पर फिर नया टैरिफ लगाने की बात कर दी। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में एक कार्यक्रम के दौरान 12 बिलियन डॉलर की फार्म सब्सिडी की घोषणा करते हुए कहा कि वे भारत, वियतनाम और थाईलैंड जैसे देशों से 'डिपिंग' की जा रही चावल की समस्या का समाधान करने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा कनाडा से आने वाली खाद पर भी अमेरिका एक्सट्रा टैरिफ लगाने पर विचार कर रहा है। इसके पीछे लॉजिक दिया जा रहा है कि वे अपने किसानों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। ट्रंप अगर भारतीय चावल पर टैरिफ लगाते हैं तो इससे चावल अमेरिका भेजना मुश्किल होगा। ऐसे में किसानों को आर्थिक नुकसान हो सकता है। थिंक टैंक ने कहा, यह धमकी पॉलिटिक्स है, पॉलिसी नहीं। जीटीआरआई ने कहा कि अगर अमेरिका ने टैरिफ को बढ़ाया भी, तो उसका भारतीय निर्यात पर सीमित ही असर होगा, क्योंकि भारत के चावल की मांग वैश्विक स्तर पर मजबूत है, खासकर अमेरिका में। बड़े हुए दामों का असर अमेरिकी उपभोक्ताओं पर पड़ेगा, क्योंकि वे भारतीय बासमती और प्रीमियम चावल पर निर्भर हैं। इसलिए भारत को अमेरिका की इस धमकी से घबराने की जरूरत नहीं है। बता दें कि भारत दुनिया का सबसे ज्यादा चावल उत्पादक और नंबर वन निर्यातक देश भी है। भारतीय चावल निर्यातक संघ के मुताबिक भारत सालाना 15 करोड़ मीट्रिक टन चावल का उत्पादन करता है जो दुनिया भर के चावल उत्पादन का 28 प्रतिशत है। 2024-25 में भारत दुनिया भर में सबसे ज्यादा चावल निर्यात करने वाला देश रहा। इस दौरान दुनिया भर के कुल चावल निर्यात का 30.3 प्रतिशत हिस्सा भारत का रहा। चावल उत्पादन के मामले में दूसरे नंबर पर चीन है। उसका सालाना चावल उत्पादन करीब 14 करोड़ मीट्रिक टन है। इस सूची में थांलादेश, इंडोनेशिया, वियतनाम, थाईलैंड और पाकिस्तान का नाम भी शामिल है। भारत में बासमती, सबसे ज्यादा निर्यात की जाने वाली चावल की किस्मों में से एक है।



गोवा अग्निकांड उमेश चतुर्वेदी

गोवा में साल के आखिरी दिनों और अगले साल की छुट्टियां मनाने का मन बना चुके सैलानियों के मन में इस बार हिचक हो सकती है। वजह है, यहां के मशहूर नाइट क्लब बर्क बाय रोमियो लेंन में लगी आग, जिसमें पांच सैलानी समेत पच्चीस लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। दुर्घटनाएं कह कर नहीं आतीं, लेकिन उनकी रोकथाम की मुकम्मल तैयारी से शायद ही किसी को इनकार हो, गोवा के इस नाइट क्लब में लगी आग और उसमें गई निर्दोष जानों ने सबसे बड़ा सवाल उस प्रशासनिक तंत्र पर लगाया है, जिस पर इस हादसे की रोकथाम की जिम्मेदारी थी। बताया जा रहा है कि अनधिकृत ढंग से इस नाइट क्लब का निर्माण किया गया था। इस अनधिकृत निर्माण को तोड़ने के लिए गोवा की संबंधित पंचायत ने निर्देश भी दे दखा है। आग लगने की दशा में उसके रोकथाम और बचाव को लेकर इस नाइट क्लब में कोई मुकम्मल इंतजाम नहीं था। इतना ही नहीं, यह क्लब बेहद संकरी जगह पर है, जहां आसानी से जाना संभव नहीं है।

उत्तर भारत की सर्दियां गोवा के लिए वरदान होती हैं। अरब सागर तटीय इस राज्य में सर्दियों में उत्तर भारतीय सैलानियों की आवक बढ़ जाती है, लेकिन हो सकता है कि इस बार यह आवक कम हो। गोवा में साल के आखिरी दिनों और अगले साल की छुट्टियां मनाने का मन बना चुके सैलानियों में इस बार हिचक हो सकती है। वजह है, यहां के मशहूर नाइट क्लब बर्क बाय रोमियो लेंन में लगी आग, जिसमें पांच सैलानी समेत पच्चीस लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। दुर्घटनाएं कह कर नहीं आतीं, लेकिन उनकी रोकथाम की मुकम्मल तैयारी से शायद ही किसी को इनकार हो, लेकिन समंदर के किनारे से इनकार आती योशानियों के बीच स्थित गोवा के इस नाइट क्लब में लगी आग और उसमें गई निर्दोष जानों ने सबसे बड़ा सवाल उस प्रशासनिक तंत्र पर लगाया है, जिस पर इस हादसे की रोकथाम की जिम्मेदारी थी। बताया जा रहा है कि अनधिकृत ढंग से इस नाइट क्लब का निर्माण किया गया था। इस अनधिकृत निर्माण को तोड़ने के लिए गोवा की संबंधित पंचायत ने निर्देश भी दे दखा है। आग लगने की दशा में उसके रोकथाम और बचाव को लेकर इस नाइट क्लब में कोई मुकम्मल इंतजाम नहीं था। इतना ही नहीं, यह क्लब बेहद संकरी जगह पर है, जहां आसानी से जाना संभव नहीं है।



रूपरेखा को लेकर चर्चा की थी। उसने इस पर गंभीर विमर्श किया था। संविधान सभा में प्रशासनिक तंत्र पर व्यापक चर्चा हुई, जिसका उद्देश्य एक ऐसा ढांचा तैयार करना था जो स्वतंत्र भारत के लिए प्राचीन, निष्पक्ष और लोकतांत्रिक सिद्धांतों के प्रति जवाबदेह हो। संविधान सभा के सदस्यों को संदेह था कि भारत की भावी नौकरशाही भारतीय मूल्यों और भारतीय व्यवस्था के अनुरूप नहीं हो पाएगी। इसी लिए संविधान सभा में तत्कालीन सदस्यों ने नौकरशाही की भूमिका पर ना सिर्फ व्यापक चर्चा की, बल्कि उसकी राजनीतिक तटस्थता, कार्यक्षमता, जवाबदेही और नए स्वतंत्र राष्ट्र के लोकतांत्रिक ढांचे में उसकी स्थिति सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया। इन बहसों का उद्देश्य एक ऐसी सिविल सेवा प्रणाली स्थापित करना रहा, जो संविधान के सिद्धांतों के प्रति निष्ठावान हो और लोगों की सेवा के लिए प्रतिबद्ध हो।

उसका ध्यान ज्यादातर अपनी ताकत को बचाए रखने और उसके जरिए आर्थिक साम्राज्य खड़ा करने पर है। भारत का शायद ही कोई राज्य हो, जहां की नौकरशाही में अकृत संपत्ति के मालिक, भ्रष्टाचारी और कर्त्तव्यहीन अफसर ना होंगे। मध्य प्रदेश जैसे जिन राज्यों में लोकपाल व्यवस्था कायम है, वहां आए दिन ऐसे अफसरों पर छापे पड़ते हैं, उनके घर मिले नोटों को गिनने के लिए मशीनों लानी पड़ती हैं। कई बार तो नोट गिनने में ही थो-थो तीन-तीन दिन लग जाते हैं। सवाल यह है कि क्या अफसरों के पास अकृत धन उनके सत्कर्मों और कर्त्तव्यपरायणता के चलते आता है? निश्चित रूप से इस सवाल का जवाब नहीं है। पैसे आते हैं, अवैध निर्माण को बढ़ावा देने से, नियमों की अवहेलना करने वालों से मिलने वाली रकम से, लोक के लिए आए फंड की बंदरबांट से। बिना प्रशासनिक मिलीभगत के यह कल्पना बेकार है कि किसी नाइट क्लब में अवैध निर्माण होगा, वह संकरी गलियों में चलेगा और उसमें सुरक्षा के इंतजाम नाकाफी होंगे। हाल के दिनों में सड़कों पर बसों के आग का गोला बनने की घटनाएं भी बढ़ी हैं, अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर भी चले हैं या चल रहे हैं, सवाल यह है कि क्या खटारा बसें बिना प्रशासनिक मिलीभगत और लापरवाही से सड़कों पर चल सकती हैं, क्या अवैध निर्माण बिना प्रशासनिक सहयोग के हो सकता है, निश्चित तौर पर ऐसे सवाल का जवाब ना में है। जब भी हादसे होते हैं, जब कोई बस आग का गोला बनती है, जब अवैध निर्माण सामने आता है, संबंधित बस मालिक के खिलाफ कार्रवाई हो जाती है, अवैध निर्माण गिरा दिया जाता है, लेकिन इन सबके लिए प्रशासनिक रूप से जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। वे साफ बच जाते हैं। आज जरूरत इस बात की है कि अब हर गलत कार्य के लिए, गलत कार्य करने वाले, नियम तोड़ने वाले, कानून का उल्लंघन करने वाले को दोषी ठहराने की न्यायिक प्रक्रिया तो चले ही, साथ ही उसके लिए परीक्षा या प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार रहे अधिकारियों को भी जवाबदेह बनाया जाए, उन्हें खोजकर उचित प्रशासनिक और कानूनी प्रक्रिया के जरिए दंडित किया जाए। जब तक का उद्देश्य नहीं किया जाता, तब तक देश में ऐसी निर्दोष जानें जाती रहेंगी, सड़कों पर अव्यवस्था फैली रहेगी, नियमों की अनदेखी से अराजकता बनी रहेगी। लेकिन लाख टके का सवाल यह है कि क्या इस तरीके से सोचने को हमारा राजनीतिक ढांचा तैयार है?

(लेखक स्वर्ण चक्रवर्ती हैं, वे उनके अनेक विचार हैं।)

बदलती भाषा मानसी द्विवेदी



हिंग्लिश से संचार तो सरल पर

हिंदी की शुद्धता पर बड़ा सवाल

आज के तकनीकी युग में जब डिजिटल क्रांति ने भाषा के स्वरूप और उपयोग को गहराई से प्रभावित किया है, हिंदी की स्थिति और उसके भविष्य पर गंभीर विचार आवश्यक हो गया है। सवाल यह है कि क्या हम हिंदी को उसकी मूल पहचान के साथ आगे बढ़ा पा रहे हैं या फिर उसे एक मिश्रित बोली के रूप में स्वीकार कर चुके हैं। इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए हिंदी के इतिहास, वर्तमान और चुनौतियों पर दृष्टि डालना जरूरी है। हिंदी का इतिहास अत्यंत समृद्ध और विस्तृत है। इसकी जड़ें संस्कृत से जुड़ी हैं और अपभ्रंश भाषाओं के माध्यम से इसका क्रमिक विकास हुआ। 7वीं शताब्दी में सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है, जबकि चंद्रबरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण कृति है। मध्यकाल के हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, जब कबीर, तुलसीदास, सुरदास और मीराबाई जैसे संत-कवियों ने इसे जन-जन तक पहुंचाया। तुलसीदास की रामचरितमानस और सुरदास का सुरसागर घर-घर में पढ़े और गाए गए। 19वीं शताब्दी में भारतेन्दु हरिश्चंद्र ने आधुनिक हिंदी की नींव रखी और प्रेमचंद, प्रसाद, पंत और निराला जैसे साहित्यकारों ने इसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हिंदी ने राष्ट्र एकजुट करने में अहम भूमिका निभाई और 1950 में इसे संविधान द्वारा प्रभावी का दर्जा मिला। आज यह विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है और भारत के बाहर भी अनेक देशों में इसकी उपस्थिति है।

इंटरनेट और स्मार्टफोन ने इसे वैश्विक मंच प्रदान किया। यूट्यूब, ब्लॉग्स, पॉडकास्ट और सोशल मीडिया पर हिंदी सामग्री की बाढ़ देखी जा सकती है। गुगल असिस्टेंट और चैटबॉट्स जैसी सेवाएं भी अब हिंदी में उपलब्ध हैं, जिससे यह तकनीकी रूप से सक्षम बनी है। पर इसी बीच एक नई भाषा-शैली का उद्भव हुआ-हिंग्लिश। हिंग्लिश का आरंभ औपनिवेशिक काल से माना जा सकता है, जब अंग्रेजी प्रशासन और शिक्षा की भाषा बनी और धीरे-धीरे बोलचाल में अंग्रेजी शब्दों की पैठ हुई। स्वतंत्रता के बाद यह मिश्रण और तेज हुआ। लेखिका शोभा डे ने अपने लेखन में इसका प्रयोग कर इसे साहित्यिक मानता दी। 1990 का दशक हिंग्लिश के प्रसार का निर्णायक काल था। इस दशक में एक टीवी चैनलों और विज्ञापनों ने कम अंश इंडिया, बोले इंग्लिश! जैसे नारे दिए और हिंदी धारावाहिकों व फिल्मों ने सेवाओं में अंग्रेजी का प्रयोग बढ़ाया, तब हिंग्लिश मुख्यधारा में प्रवेश कर गई। इस समय टीवी ने अपने धारावाहिकों और विज्ञापनों में अंग्रेजी शब्दों को मिलाना शुरू किया। हसरत, अस्तिव और लव स्टोरी जैसे शीर्षक दर्शकों को नए भाषा-रूप से परिचित कराते थे। वहीं एम टीवी और चैनल वी ने एंकरिंग और म्यूजिक शो में हिंग्लिश को युवाओं की जीवन्शीली का प्रतीक बना दिया। 21वीं सदी में इंटरनेट और मोबाइल फोन ने इसे और मजबूती दी। रोमन लिपि में हिंदी टाइप करने की आदत ने हिंग्लिश को डिजिटल भाषा का दर्जा दे दिया। आज चलो पार्टी करते हैं या तुमने फाइल अपलोड की? जैसे वाक्य बेहद सामान्य हो गए हैं। हिंग्लिश संचार को सरल तो बनाती है, लेकिन हिंदी की शुद्धता पर प्रश्नचिह्न खड़े करती है।

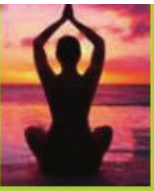
इस बीच शिक्षा और रोजगार में अंग्रेजी के गहरे प्रभाव ने हिंदी के भविष्य को और कठिन बना दिया है। अधिकांश अभिभावक अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाना ही सफलता की कुंजी मानते हैं। परिणामस्वरूप हिंदी माध्यम के छात्र अक्सरों से वंचित हो जाते हैं और हिंदी धीरे-धीरे घर और बोलचाल तक सीमित होती जा रही है। हालांकि, सरकार इसे स्थिति को सुधारने की कोशिश कर रही है। नई शिक्षा नीति के तहत चिकित्सा और इंजीनियरिंग जैसे पाठ्यक्रम हिंदी सहित भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में एमबीबीएस और इंजीनियरिंग की कितनी हिंदी में प्रकाशित कराई गई हैं। यह कदम सराहनीय हैं, पर इन्हें व्यापक स्तर पर लागू करना जरूरी है ताकि उच्च शिक्षा और शोध के क्षेत्र में हिंदी अंग्रेजी के बराबर खड़ी हो सके। हिंदी का भविष्य केवल नीतियों पर निर्भर नहीं करता। समाज को भी अपनी भाषा पर गर्व करना होगा और इसे बोझ या हीनता का प्रतीक मानने के बजाय सांस्कृतिक अस्मिता और बौद्धिक शक्ति का प्रतीक समझना होगा। हिंदी की जीवंतता इसी में है कि उसने हर युग के परिवर्तनों को आत्मसात किया है। तकनीकी दौर में भी यदि इसे शिक्षा, व्यवसाय और विज्ञान के क्षेत्र में सम्मानजनक स्थान दिया जाए तो यह न केवल अपनी पहचान बनाए रखेगी बल्कि और सशक्त होकर उभरेगी।

(लेखिका शिवांगी हैं, वे उनके अनेक विचार हैं।)

आत्मबल के लिए ईश्वर के सान्निध्य में जाएं



जब व्यक्ति किसी कार्य को करने चलता है, तो उसके मन-हृदय में बारंबार विचार-भाव उठते हैं कि वह कार्य करें या नहीं, उससे होगा या नहीं और परिणाम भी सफलता और असफलता के रूप में सामने आता है। किसी कार्य को करने के लिए बल की आवश्यकता होती है।



संकलित दर्शन

हालांकि इसका ज्ञान उसका गीत दाना असम्भव है। कई बार किसी कार्य का करत सम्यक् नाना-प्रकार के संकट उसमें बाधा बन खड़े हो जाते हैं। ऐसे में कोई व्यक्ति उस कार्य को बीच में ही छोड़ देता है। परिणामस्वरूप उसे असफलता हाथ लगती है। असफलता यह सिद्ध करती है कि अमुक कार्य को पूरे मनोयोग से नहीं किया गया। मनोयोग का अर्थ होता है-तन, मन और हृदय से समर्पित होकर किसी कार्य को करना। किसी कार्य में सफल होने के लिए व्यक्ति में मानसिक संतुलन, विश्वास, जिज्ञासा, लगन, संघर्ष करने की क्षमता और तन्मयता जैसे गुणों का होना जरूरी होता है। इनकी प्राप्ति आत्मबल से होती है। आत्मबल की प्राप्ति के लिए ईश्वर के सान्निध्य में जाना पड़ता है। सान्निध्य पाने के लिए ईश्वर का विश्वास आवश्यक है। विश्वास पाने के लिए तप-साधना करनी पड़ती है। चूंकि आत्मबल में ईश्वर की शक्ति निहित होती है, इसलिए इसे ब्रह्मबल भी कहते हैं। आत्मबल से संपन्न मनीषी के लिए कोई कार्य असंभव नहीं रहता है। उसका कोई कार्य बीच में नहीं रुकता है। जब शरीरबल और मनोबल टूट जाता है तो उस समय आत्मबल सहाय देता है। आत्मबल से युक्त व्यक्ति की प्रवृत्ति-निराश नहीं होता है।

सटाका



करंट अफेयर

हम 'क्वाड' के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं : रुबियो

अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा कि अमेरिका 'क्वाड' के प्रति 'पूरी तरह प्रतिबद्ध' है तथा अपने वाले वर्षों में इस समूह को और मजबूत करेगा। 'क्वाड' (चतुष्पक्षीय सुरक्षा संवाद) अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया का एक समूह है। रुबियो ने सोमवार को कहा, 'हम क्वाड के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। आने वाले समय में जापान और भारत के साथ मिलकर इसे आगे बढ़ाने के लिए और काम करेंगे...।' ऑस्ट्रेलिया- अमेरिका मंत्रिस्तरीय वार्ताओं से पहले उन्होंने रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ, ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री एव' रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्शल तथा ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वोग की मौजूदगी में विदेश मंत्रालय में संयुक्त बयान देते हुए यह बात कही। रुबियो के अनुसार, इस साल जनवरी में विदेश मंत्री के रूप में शपथ लेने के तुरंत बाद क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक उनकी पहली आधिकारिक बैठक थी। उन्होंने कहा, 'मेरे नाम पर मुहर लगी, मैंने नीचे शपथ ली और सीधे इसी लिफ्ट से ऊपर आकर इस कक्ष में पहुंचा। विदेश मंत्री के रूप में मेरा पहला कार्यक्रम यहीं इसी कक्ष में क्वाड के साथ हुआ था।' रुबियो ने कहा, जहां तक मुझे याद है, इस साल हमारी कम से कम तीन बैठकें हुई हैं।



आज की पाती

आशा की किरण है यह बिल
सांसद सुधिया सुते द्वारा लोकसभा में पेश किया गया राष्ट्र टूट डिस्कनेक्ट बिल 2025 देश के करोड़ों कर्मचारियों के लिए आशा की किरण लेकर आया है। यह बिल कहता है कि ऑफिस समय के बाद कोई भी कर्मचारी अपने बॉस, मैनेजर या संस्थान के कॉल, ईमेल, मैसेज या किसी डिजिटल निदेश का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं होगा। यदि यह कानून बनता है, तो भारत की कार्य-संस्कृति में एक ऐतिहासिक परिवर्तन संभव है। लेकिन इसका विरोध, इसकी चुनौती, इसका व्यावहारिक पक्ष और इसका सामाजिक प्रभाव-ये सभी उतने ही महत्वपूर्ण सवाल हैं, जिनका विस्तारपूर्ण चर्चा जरूरी है। आज यह एक प्रशासनिक या तकनीकी मुद्दा मात्र नहीं, बल्कि स्वास्थ्य संकट से जुड़ा विषय है।
-मनोज जोशी, विलासपुर

ऑफ बीट

महासागर पहले कभी हरे रंग के हुआ करते थे

महासागर धरती के करीब तीन चौथाई हिस्से पर फैले हैं जिससे यह ग्रह आकाश से हल्के नीले रंग का दिखता है। लेकिन 'नेचर पत्रिका' में प्रकाशित एक अध्ययन रिपोर्ट में जापानी शोधकर्तओं ने यह दावा किया है कि पृथ्वी के महासागर कभी हरे हुआ करते थे। प्राचीन काल में पृथ्वी के महासागरों के अलग रंग में दिखने का संबंध उनके रसायन विज्ञान और प्रकाश संश्लेषण के विकास से है। भूविज्ञान के स्नातक छात्र के रूप में, मुझे यह के इतिहास को रिकॉर्ड करने के लिए जिनसे 'बैडड आयरन' संरचना के रूप में जाने जाने वाले एक प्रकार के 'चट्टानी जमाव' के महत्व के बारे में पढ़ना गया था। 'बैडड आयरन' संरचना का जमाव आर्कियन और पैलियोप्रोटोरोजोइक युग में लगभग 3.8 से 1.8 अरब साल पहले हुआ था। उस समय जीवन महासागरों में एक कोशिका वाले जीवों तक ही सीमित था। महाद्वीप, भूरे और काले रंग की चट्टानों और जमा तलछटों का एक बंजर परिदृश्य था। महाद्वीपीय चट्टानों पर गिरने वाली बारिश की बूंदों से उसमें विद्यमान लोहा घुलकर नदियों के जरिये महासागरों में पहुंच गया। लोहे के अचूक स्रोत समुद्र तल पर ज्वलामुखी थे। यह लोहा (आयरन) बद में महत्वपूर्ण हो गया होगा।

ट्रेंड्स

जल्द सार्थक परिणाम आएंगे

सरकार अमेरिका के टैरिफ उपायों के भारतीय निर्यात पर असर को कम करने के लिए लयाचर काम कर रही है। इसके लिए एक बहुपक्षीय राजनीतिक आलवर्ग जा रही है। जल्द इसके सार्थक परिणाम आने शुरू हो जाएंगे।
-नितिन शर्मा, वाराणसी और उद्योग राज्य मंत्री

हमारे पास अधिकार नहीं

यहां हम कोई क्षेत्र छोड़ें पर शिष्ट व्यवहार रहे है? कृष्ण के अनुभव, हमारे पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है। यूक्रेन के कानून, हमारे संचिपण, अंतरराष्ट्रीय कानून और, तब कहें तो, हमारे पास नैतिक अधिकार भी नहीं है।
-वीलेंटीन जेलेस्की, राष्ट्रपति यूक्रेन

23 अरब डॉलर का निवेश

नाइक्रोसाइट आईई में भारत में 23 अरब डॉलर का निवेश करेगी। यह नाइक्रोसाइट द्वारा इस साल की कुरुआत में घोषित तीन अरब डॉलर के निवेश पर आधारित है। इसके कर्तव्यों को भारत में सबसे बड़ी विलासुड मौजूदगी मिलेगी, जिसमें पहला डेटा नोट 2026 के मध्य में जारी हो जाएगा।
-सत्या नडेला, सीईओ, नाइक्रोसाइट

विकास पथ तैयार करना होगा

21वीं सदी में भारत की सामाजिक, प्रभुत्विक संरचनाएं एवं ऊर्जा प्रणालियां पर उल्लेख निरंतरता पर निर्भर करेगी। भारत को एक ऐसे दिव्य में, जहां स्तरीय आत्म-संस्था और वैश्विक गठबंधनों में टकरा बढ़ती जा रही है, अपना विकास पथ स्वयं तैयार रखना होगा।
-गौतम अटवाणी, चेयरमैन, अटवाणी समूह



खबर संक्षेप

आवारा कुत्तों को एनिमल लवर्स के घर छोड़ दें

मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने आवारा कुत्तों के बंदते खतरों और हमलों से निपटने के लिए विधायकों के साथ बैठक करने पर सहमति व्यक्त की। भोसरी से भाजपा विधायक महेश लांडगे ने मांग की कि हमला करने वाले कुत्तों को 'पकड़कर सीधे एनिमल लवर्स के घरों में छोड़ देना चाहिए। ताकि, उन्हें समस्या की गंभीरता का अहसास हो सके।

गाय को खिलाया चिकन मोगोज, गिरफ्तार

गुरुग्राम। यहाँ के सेक्टर-56 थाना क्षेत्र में गाय को चिकन मोगोज खिलाने पर युवक को पीटने का मामला सामने आया है। गोरक्षकों ने युवक को जमकर धुलाई कर पुलिस के हवाल कर दिया। युवक सोशल मीडिया एप पर मिले टास्क पर मोमोज खा रहा था। पुलिस ने युवक पर केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया है।

महाराष्ट्र विधानसभा में तेंदुआ बने विधायक

मुंबई। तस्वीर में तेंदुआ में गेटअप में दिख रहे शब्द महाराष्ट्र के माननीय हैं और वे इस शि-भूषा में बुधवार को महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर नजर आए। जुन्नार के विधायक शरद सोनावणे को देखकर कुछ देर के लिए कौतुहल मच गया। थोड़ी देर बाद जब विधायक ने बातें रखीं तो समझ आई। उन्होंने तेंदुआ के बंदते हमलों के विरोध में ऐसा किया।

बागपत में फैक्ट्री से 300 किलो माल नष्ट किया

बागपत। यूपी का बागपत शहर क बीचों-बीच चल रही नकली खाने के एक बड़े रैकेट का खाद्य विभाग ने शंका जताई है। यहाँ एक गोदाम से सैकड़ों किलो घटिया और सेहत के लिए खतरनाक मेयोनीज और सांस फास्ट-फूड की दुकानों में भेजी जा रही थी। विभाग ने 300 किलो से अधिक नकली मेयोनीज नष्ट कर दी।

दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान केंद्र और डीजीसीए की कड़ी आलोचना की 5000 का टिकट 39 हजार का कैसे हो गया यात्रियों को परेशानी की भरपाई करे इंडिगो

एजेसी नई दिल्ली

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को इंडिगो एयरलाइंस के चल रहे संकट पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) की कड़ी आलोचना की। हाई कोर्ट ने इंडिगो की फ्लाइट कैसिलेशन और देरी की बढ़ती घटनाओं को गंभीर संकट बताते हुए केंद्र से सवाल किया है कि आखिर हालात इस कदर कैसे बिगड़ गए? कोर्ट ने निदेश दिया है कि यात्रियों को तुरंत मुआवजा देने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं।

सैकड़ों फ्लाइट्स कैसिल होने से प्रभावित यात्रियों के लिए मदद और रिफंड की मांग करने वाली एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कहा कि इंडिगो की उड़ानें रद्द होने से न सिर्फ यात्रियों को परेशानी और उपीड़न का सामना करना पड़ा, बल्कि इससे अर्थव्यवस्था को भी नुकसान हो रहा है। कोर्ट ने सवाल उठाया कि जब इंडिगो की फ्लाइटें बंद थीं, तो अन्य एयरलाइंस ने मौके का फायदा उठाते हुए टिकटों के दाम क्यों बढ़ा दिए? कोर्ट ने पूछा कि दूसरी एयरलाइंस के दाम बढ़ाने को कैसे जायज ठहराया जा सकता है।

इंडिगो की फ्लाइट कैसिलेशन और देरी की घटनाओं को गंभीर माना

यात्रियों की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता

दाम बढ़ाने को जायज नहीं ठहराया जा सकता उच्च न्यायालय ने विमानन कंपनी को दिया निर्देश



दिल्ली हाईकोर्ट

चीफ जस्टिस वेदेंद्र कुमार उपस्थित और जस्टिस तुषार राव मेंडोता की बीच में कहा कि पायलटों के लिए संशोधित फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (एफडीटीएल) नियमों को लागू करने में देरी और निगरानी की कमी के कारण देशभर में 2,000 से अधिक उड़ानें रद्द हुईं और 40,000 से ज्यादा यात्री फंस गए। अखिल ने टिप्पणी की कि यात्रियों की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता। पायलटों की थकान से दुर्घटना का खतरा बढ़ता है। नियामक संस्थाओं को पहले से सक्रिय कदम उठाने चाहिए।

टिकटों में बेतहाशा वृद्धि कैसे हो गई?

कोर्ट ने यह भी नाराजगी जताई कि उड़ानें रद्द होने के बाद अन्य एयरलाइंस ने किराया 40 हजार तक बढ़ा दिया। क्या यह अवसरवाद नहीं है? दूसरी एयरलाइंस को फायदा उठाने की इजाजत कैसे दी जा सकती है? जो टिकट 4-5 हजार में मिलते थे, उनके दाम इतने कैसे बढ़ गए?

मुआवजे में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी

अदालत ने स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रभावित सभी यात्रियों को डीजीसीए के मौजूदा दिशा-निर्देशों और भारतीय वायुयान अधिनियम, 2024 के तहत मुआवजा दिया जाए। कोर्ट ने मुआवजा सिर्फ कैसिलेशन के लिए नहीं, बल्कि यात्रियों को हुई परेशानी के लिए भी होना चाहिए। किराए में कोताही नहीं हो।

सरकार ने कोर्ट में कही ये बात

केंद्र और डीजीसीए की ओर से पेश वकील ने अदालत को बताया कि इस मामले में कानूनी प्रक्रिया पूरी तरह लागू है और इंडिगो को शो-काऊ नोटिस जारी किया जा चुका है।

22 जनवरी को होगी अगली सुनवाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, हमने इस आदेश में आपके (इंडिगो) बारे में फिलहाल कुछ नहीं कहा है, लेकिन जहाँ तक बर्दाश्त की बात है, तो यह आपके तुरंत करना चाहिए। मुआवजा व सिर्फ रद्द उड़ानों के एरर में मिले, बल्कि यात्रियों को हुई पीड़ा को भी बर्दाश्त हो। कोर्ट ने निर्देश दिया कि 22 जनवरी, जो अगली सुनवाई की तारीख है, तक अंतर किसी कमेंटी द्वारा शुरू की गई जाय पूरी हो जाती है, तो उसकी रिपोर्ट जौलबंद लिफाफे में कोर्ट में जमा की जाए। वेंच ने इस मामले को डेढ़ घंटे से ज्यादा समय तक जुगा।

बाराबंकी में 2 कारों में मिड़त

गेट न खुलने से 5 जिंदा जल गए गुहार लगाते रहे पर मदद न मिली



सड़क पर धक्कती कार और अंदर जल गए लोग

एजेसी बाराबंकी

लग गया। पुलिस की टीम मौके पर

5,000 रु. जुमाना, 3 साल की कैद या दोनों सजाएं होंगी

बुरे असर को प्रभावी ढंग से रोकने और नियंत्रित करने की कोशिश



एजेसी बैंगलूर

कर्नाटक में हेट स्पीच रोकथाम बिल को मिली मंजूरी

विधानसभा के शीतकालीन सत्र में इस बिल को मंजूरी मिली

नुकसान, नफरत फैलाना या उकसाना माना जाएगा दोष

ये रखे गए सजा के प्रावधान

- कोई भी व्यक्ति जो किसी व्यक्ति के धर्म, जाति, समुदाय, लिंग, यौन रुझान, उम्र, स्थान, निवास, भाषा, विकलांगता या जनजाति के प्रति अपने पूर्वाग्रह या असहिष्णुता के कारण किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाता है या नुकसान पहुंचाने के लिए उकसाता है या नफरत फैलाना है, यह हेट काइडम का दोषी माना जाएगा।
कोई भी हेट काइडम करेगा, उसे तीन साल तक की कैद या 5,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। हेट काइडम का अपराध गैर-संज्ञेय और गैर-जमानती होगा और इसकी सुनवाई फास्ट ट्रैक मजिस्ट्रेट द्वारा की जाएगी।
कोई भी व्यक्ति जो जान-बूझकर कुछ भी प्रकाशित करता है, प्रसारित करता है या उम्रथल करता है या एक या ज्यादा लोगों को इस तरह से बात करता है जिससे यह साफ तौर पर लगे कि उसका इरादा धर्म, जाति, भाषा, समुदाय और अन्य संज्ञित इन आसरो में से किसी एक के आधार पर नुकसान पहुंचाना या नुकसान पहुंचाने के लिए उकसाना या नफरत फैलाना है, वह सजा का हकदार होगा।
इसमें वैसे व्यक्ति भी शामिल होंगे जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन पर ऐसी चीजें प्रोड्यूस करते हैं या उपलब्ध कराते हैं, जो कोई भी एक्सेस कर सकता है और साथ ही किसी खास व्यक्ति तक पहुंचाई जाती है या उसे निर्दिष्ट की जाती है जिसे हेट स्पीच का शिकार माना जा सकता है।

तेलंगाना में 1000 करोड़ का फंड होगा

हैदराबाद को यूनिवर्सल हब बनाने की तैयारी

हैदराबाद। तेलंगाना सरकार स्टार्टअप को समर्थन देने के लिए 1000 करोड़ का फंड स्थापित

कर रही है। राज्य के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी बुधवार को गूगल फॉर स्टार्टअपस हब की शुरुआत के मौके पर बोल रहे थे, जो तेलंगाना सरकार के साथ साझेदारी में शुरू किया गया है। रेड्डी ने दावा किया कि आने वाले वर्षों में कम से कम 100 हैदराबाद-आधारित स्टार्टअपों को यूनिवर्सल स्तर, अपनी कम से कम 1,000 करोड़ रुपये मूल्यांकन, तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि मेरा एक ही सुझाव है कि आपको हैदराबाद, तेलंगाना से एक और गुगल बनाना होगा या कम से कम एक अरब अमेरिकी डॉलर की कंपनी बनाना होगा।

न्यायालय, द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश महोदय, अम्बिकापुर जिला- सरगुजा (छ.ग.) विव्यद, वादक. 111/2024 प्रो. नं. - 912/25 सेतराम प्रति दिलराज व अन्य ईशतहार आम जनता, ग्राम फुनगी (रामनगर), तहसील उदयपुर, जिला सरगुजा (छ.ग.) को सूचित किया जाता है, कि आवेदक सेतराम द्वारा अपने पितामह स्व कबीर दास आ. स्व. सहदेव पंिका, निवासी, ग्राम फुनगी (रामनगर), तहसील उदयपुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.) स्थित भूमि खसरा क्र. 53/15/53/17, 70/2, 71/3, 171/2011 कुल रकबा 1.962 हेक्टेयर भूमि का पंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 08/11/2023 को आवेदक सेतराम के पक्ष में निष्पादित एवं पंजीकृत किया गया है। आवेदक सेतराम द्वारा इस न्यायालय में प्रोबेट प्रमाण पत्र जारी करने हेतु आवेदन अंतर्गत धारा 276 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के तहत विविध वाद प्रस्तुत किया गया है। उक्त संबंध में किसी भी व्यक्ति, संस्था को आपत्ति होने पर अपनी लिखित आपत्ति इस मामले में अपना पक्ष रखने हेतु स्वयं अथवा अपने अधिकृत अधिकारक के माध्यम से पेशी दिनांक 27-01-2026 को इस विविध वादक्र. 0/11/2024 में द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायालय, अम्बिकापुर के समक्ष समय प्राप्त: 11.00 बजे उपस्थित होकर अपना पक्ष रखे। प्रकरण में उक्त पेशी दिनांक एवं समय पर दावा/आपत्ति प्राप्त न होने पर मामले में अग्रिम वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी। यदि किसी कारणवश उक्त पेशी तिथि को सार्वजनिक अवकाश अथवा पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर होने की स्थिति में आगामी कार्य दिवस पर मामले को सुनवाई की जावेगी। अतः दिनांक 11/12/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया। (श्री मुकुंश कुमार तिवारी) द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश अम्बिकापुर, सरगुजा (छ.ग.)

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बलरामपुर जिला बलरामपुर- रामानुजगंज (छगं) --: ईशतहार:-- नगरपंचायत बलरामपुर थाना व तहसील बलरामपुर जिला बलरामपुर- रामानुजगंज (छ.ग.) एतद् द्वारा सर्वसाधारण नगर पंचायत बलरामपुर को सूचित किया जाता है। कि आवेदिका जासमीन खातून पिता असलम खान निवासी ग्राम बलरामपुर थाना व तहसील बलरामपुर जिला बलरामपुर रामानुजगंज (छ.ग.) के द्वारा अपने नाम आसमीन खातून से परिवर्तित कर नया नाम शासमीन खातून के नाम से समस्त शासकीय, अद्विशासकीय, निकाय, बैंकिंग अभिलेख राजस्व अभिलेख आधार कार्ड एवं अन्य दस्तावेज व प्रमाण पत्रों में दर्ज कराने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। उपरोक्त आवेदन पत्र के आधार पर हल्का पटवारी, पटवारी हल्का नंबर 18, तहसील बलरामपुर से जांच प्रतिवेदन मंगाया गया। आवेदिका के 5 वीं 8 वीं 10 वीं एवं 12 वीं के अंकसूची में नाम जासमीन खात ही है एवं वर्तमान में आवेदिका जासमीन खातून पिता असलम खान का निवात अब्दुल कलाम वाई ग्राम बलरामपुर में मकान बनाकर निवासरत है। यदि उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई आपत्ति हो, तो निधिर्त सुनवाई तिथि 23/12/2025 को मेरे न्यायालय में अथवा अधीक्षक भू-अभिलेख के कार्यालय में स्वयं अथवा अपने अधिकारक के माध्यम से उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। निधिर्त समवाधि के पश्चात प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 02/12/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी। अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बलरामपुर

जिला स्तरीय समीक्षा समिति/जिला सलाहकार समिति की बैठक सम्पन्न

सोनभद्र। जिलाधिकारी बी०एन० सिंह ने आज कलेक्ट्रेट मीटिंग हाल में बैठक की, बैठक के दौरान जिला स्तरीय समीक्षा समिति/जिला सलाहकार समिति की बैठक की, बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि जो बैंकर्स जनमानस की सुविधा के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं, केन्द्र व प्रदेश सरकार द्वारा संचालित योजनाओं से सम्बन्धित पत्रावलियों का समय से निस्तारण नहीं कर रहे हैं और अनावश्यक तरीके से लाभार्थियों को परेशान कर रहे हैं, ऐसे बैंकर्स के विरुद्ध उच्च स्तर पर पत्राचार किया जायें।

<p>न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अम्बिकापुर, जिला सरगुजा, (छगं) ईशतहार रा०प्र०क्र०./अ-2/2025-26 एतद् द्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक निधी त्रिपाठी पत्नी संदीप त्रिपाठी जाति ब्राह्मण निवासी भगवानपुरखुर्द तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छगं) के द्वारा अपने स्वामित्व एवं आधि की भूमि स्थित ग्राम फुन्दुटीडहारी तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छगं) खसरा नंबर 434/272, 434/273 रकबा 0.040, 0.166 हे० भूमि को कृषि पिन-व्यावसायिक (हॉस्पिटल) प्रयोजन हेतु व्यवर्तन कराने के लिए भूमि को बी-1, खसरा, रजिस्ट्री की प्रति, आदि सहित आवेदन प्रस्तुत किया है। जो इस न्यायालय में विचाराधीन है। अतएव उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई आपत्ति हो, तो निधिर्त सुनवाई तिथि 23/12/2025 को मेरे न्यायालय में अथवा अधीक्षक भू-अभिलेख के कार्यालय में स्वयं अथवा अपने अधिकारक के माध्यम से उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। निधिर्त समवाधि के पश्चात प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 08/12/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी। अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अम्बिकापुर</p>	<p>न्यायालय नजूल अधिकारी अम्बिकापुर जिला-सरगुजा रा०प्र०क्र०/अ-6-अ/2025-26 ईशतहार एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक गगन गुप्ता अकाशा गुप्ता दोनो आ० सुदामा गुप्ता, भेन्ना गुप्ता आ० स्वा. सुदामा गुप्ता सभी निवासी सदर रोड अम्बिकापुर थाना व तहसील अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा (छगं) के द्वारा मोहल्ला न्यू महामाया रोड नगर अम्बिकापुर सेंट नंबर 08 स्थित नजूल प्लॉट नंबर 2602/91, रकबा 0.06 एकड़ भूमि के नजूल अभिलेखों में आवेदकगण के नाम अगे लिखे नाबालिक शब्द को विलोपित कराने हेतु सल्लता की धारा 115 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। उका के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा/आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिकारक के माध्यम से दिनांक 26/12/2025 तक इस थ्यागालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। निव्यतिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 05/12/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया नजूल अधिकारी अम्बिकापुर</p>	<p>न्यायालय तहसीलदार राजपुर, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.) रा०प्र०क्र०/अ-121/2024-25 ग्राम उलिया तहसील राजपुर --: ईशतहार:-- एतद् द्वारा सर्वसाधारण आम जनता ग्राम उलिया को सूचित किया जाता है कि आवेदक तिलसुराम आ० स्व. बालसाव जाति निवासी ग्राम थाना राजपुर तहसील राजपुर जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज (छगं) द्वारा अपने पिता स्व० बालसाव आ० दशरथ को मृत्यु ग्राम उलिया में दिनांक 25/09/2003 को हुआ है। किन्तु मृत्यु पंजीवन कार्यालय में निव्यत समय में अज्ञानता वंश कार्य व्यस्तता के कारण पंजीवन नहीं करा पाने के कारण पंजीवन हेतु आवेदन पत्र प्रेषण पत्र पेश है। जो न्यायालय में मृत्यु प्रमाण पत्र हेतु विचाराधीन है। आवेदक के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर यदि किसी अथवा अपने अभिभावक के माध्यम से पेशी तिथि 04/11/2025 के पूर्व इस न्यायालय में आपत्ति पेश कर सकता है। निव्यत दिनांक के पश्चात प्राप्त होने वाले दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 24/11/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया। अनुविभागीय अधिकारी (रा.) राजपुर जिला बलरामपुर</p>	<p>न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अम्बिकापुर, जिला सरगुजा, (छगं) ईशतहार रा०प्र०क्र०/अ-2/2025-26 एतद् द्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक एजाज अंसारी पिता नेवाजुद्दीन जाति मुसलमान निवासी चन्द्रनगर तहसील रामानुजगंज जिला बलरामपुर (छगं) के द्वारा अपने स्वामित्व एवं आधि की भूमि स्थित ग्राम श्रीगढ़ तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छगं) खसरा नंबर 105/14 रकबा 0.007 हे० भूमि को कृषि पिन-आवासीय प्रयोजन हेतु व्यवर्तन कराने के लिए भूमि को बी-1, खसरा, नजरी नक्शा, भूमि उपयोगिता प्रमाण पत्र, रजिस्ट्री की प्रति, आदि सहित आवेदन प्रस्तुत किया है, जो इस न्यायालय में विचाराधीन है। अतएव उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई आपत्ति हो, तो निधिर्त सुनवाई तिथि 23/12/2025 को मेरे न्यायालय में अथवा अधीक्षक भू-अभिलेख के कार्यालय में स्वयं अथवा अपने अधिकारक के माध्यम से पेशी दिनांक 17/12/2025 तक अपना आपत्ति इस न्यायालय में पेश कर सकते है। निव्यत तिथि के बाद प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 08/12/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी किया। अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अम्बिकापुर</p>	<p>न्यायालय नायब तहसीलदार तहसील भैयाथान जिला सूरजपुर (छगं) रा.प्र.क. ब/121 वर्ष ग्राम-झिलमिली प.ह.नं. 16 ईशतहार एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक जुरेश्वर प्रमाद पिता उमाशंकर जाति पंचांग निवासी ग्राम झिलमिली प.ह.नं. 16 रा.नि.नं. भैयाथान तहसील भैयाथान जिला सूरजपुर (छगं) द्वारा आवेदन पेश किया गया है कि आवेदक के पुत्र/पुत्री जुरेश्वर प्रमाद पिता उमाशंकर का जन्म दिनांक 15/07/1980 को ग्राम झिलमिली में हुई है। अज्ञानतावश जन्म पंजीवन नहीं करा पाया है। आवेदक अपने पुत्र/पुत्री जुरेश्वर प्रमाद पिता उमाशंकर का जन्म पंजीवन हेतु आवेदन पेश किया है। जिसके संबंध में प्रकरण इसे न्यायालय में विचाराधीन है। अतः उक्त संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो निधिर्त सुनवाई तिथि 23/12/2025 को मेरे न्यायालय में अथवा अधीक्षक भू-अभिलेख के कार्यालय में स्वयं अथवा अपने अधिकारक के माध्यम से पेशी दिनांक 17/12/2025 तक अपना आपत्ति इस न्यायालय में पेश कर सकते है। निव्यत तिथि के बाद प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 08/12/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी किया। अनुविभागीय अधिकारी (रा.) भैयाथान जिला सूरजपुर</p>	<p>न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अम्बिकापुर, जिला सरगुजा, (छगं) ईशतहार रा०प्र०क्र०/अ-2/2025-26 एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक अनुराधा पाण्डेय पत्नी शक्ति प्रताप पाण्डेय जाति ब्राह्मण निवासी लखनपुर तहसील लखनपुर जिला सरगुजा (छगं) के द्वारा अपने स्वामित्व एवं आधि की भूमि स्थित ग्राम नमनाकला तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छगं) खसरा नंबर 484/155 रकबा 0.024 हे० भूमि को कृषि पिन-आवासीय प्रयोजन हेतु व्यवर्तन कराने के लिए भूमि को बी-1, खसरा, सेटलमेन्ट, भूमि उपयोगिता प्रमाण पत्र, रजिस्ट्री की प्रति, आदि सहित आवेदन प्रस्तुत किया है, जो इस न्यायालय में विचाराधीन है। अतएव उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई आपत्ति हो, तो निधिर्त सुनवाई तिथि 23/12/2025 को मेरे न्यायालय में अथवा अधीक्षक भू-अभिलेख के कार्यालय में स्वयं अथवा अपने अधिकारक के माध्यम से उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। निधिर्त समवाधि के पश्चात प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 08/12/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी। अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अम्बिकापुर</p>
--	--	---	--	---	---

सेजस नवापारा में हेल्थ प्रोग्राम अंतर्गत मृदा स्वास्थ्य कार्ड के संबंध में दिया गया प्रशिक्षण



प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन सूरजपुर। विश्व मृदा दिवस के अवसर पर स्कूल स्वायल हेल्थ प्रोग्राम अंतर्गत मृदा स्वास्थ्य एवं मृदा स्वास्थ्य कार्ड के संबंध में यहां के पी.एम.श्री. स्वामी आत्मानंद विद्यालय नवापारा के विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को उप संचालक कृषि सुश्री सम्पदा पैकरा के मार्गदर्शन में गुरुवार को प्रशिक्षण दिया गया। जिसमें मृदा स्वास्थ्य के संबंध में मृदा स्वास्थ्य कार्ड के लाभ, महत्व एवं मृदा परीक्षण हेतु नमूना एकत्र तथा स्वायल हेल्थ कार्ड पोर्टल में ऑनलाइन प्रविष्टि करने के संबंध में कृषि विभाग के सहायक मिट्टी परीक्षण अधिकारी डॉ. तेज राम बंजारा एवं कृषि विकास अधिकारी श्रीमती ममता रानी द्वारा विस्तार से जानकारी दिया गया।

इस दौरान विद्यार्थी सीखने को उत्सुक नजर आये प्रशिक्षण को सफल बनाने में विद्यालय के विद्यार्थियों के अलावा प्राचार्य श्री मनोज कुमार झा, शिक्षक दुष्यंत राजवाड़े, श्रीमती त्रिषा गुप्ता, श्रीमती श्वेता जायसवाल, दिपिका कांत, पूजा कुशवाहा एवं कृषि विभाग के कर्मचारियों का सहयोग रहा।

स्टॉफ की कमी से जूझ रहा महली उप स्वास्थ्य केंद्र, ग्रामीण परेशान

अब तक अधूरा है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का दर्जा, कलेक्टर से व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन चांदनी बिहारपुर। क्षेत्र के महत्वपूर्ण महली उप स्वास्थ्य केंद्र की बदहाल व्यवस्था एक बार फिर सुर्खियों में है। लगभग दर्जनों गांवों की आबादी इस केंद्र पर निर्भर है, लेकिन पिछले एक वर्ष से यहां स्टाफ की भारी कमी है। गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी सेवाएं बंद हैं, ओपीडी नियमित नहीं चल पा रहा और ग्रामीणों को इलाज के लिए दूर-दराज के क्षेत्रों में भटकना पड़ रहा है। पूर्व में छत्तीसगढ़ शासन व जिला प्रशासन द्वारा महली को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने का आश्वासन दिया गया था। बताया गया था कि प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है, लेकिन दो वर्ष बीत जाने के बाद भी पीएचसी का दर्जा महली को नहीं मिल सका। इससे ग्रामीणों में गहरा असंतोष है क्योंकि पीएचसी बनने से यहां डॉक्टर, नर्स, लैब टेक्नीशियन, डिलीवरी रूम, दवाएं और चौबिस घंटे सेवाएं उपलब्ध हो सकती थीं।



कई गांवों में मोबाइल नेटवर्क ही नहीं है। एंबुलेंस कॉल न कर पाने की वजह से कई मरीजों को गंभीर स्थिति में घंटों इंतजार करना पड़ता है। महली छत्तीसगढ़ मध्यप्रदेश सीमा के पास स्थित है। स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में कई ग्रामीण मध्यप्रदेश के सिमरौली बर्बादी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। स्टाफ की मांग को लेकर युवा कांग्रेस बिहारपुर ब्लॉक अध्यक्ष जितेंद्र साकेत ने स्टाफ की कमी से परेशान ग्रामीणों की ओर से कलेक्टर सूरजपुर का ध्यानाकर्षण करते हुए आवेदन सौंपा है। ज्ञापन में मांग की गई

है कि महली उप स्वास्थ्य केंद्र में तत्काल नर्स, एएनएम ड्रेसर, कम्पाउंडर और अन्य आवश्यक स्टाफ उपलब्ध कराया जाए। केंद्र को जल्द से जल्द प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का दर्जा दिया जाए। एंबुलेंस की उपलब्धता और नेटवर्क समस्या का समाधान किया जाए ताकि आपातकालीन सेवा बाधित न हो। श्री साकेत ने कहा कि महली जैसे दूरस्थ और पहाड़ी क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधा ग्रामीणों का अधिकार है। पीएचसी का दर्जा और स्टाफ की नियुक्ति तत्काल आवश्यक है, ताकि गर्भवती महिलाएं और गंभीर मरीज समय पर उपचार पा सकें। महली व आसपास के गांवों के ग्रामीणों ने उम्मीद जताई है कि जिला प्रशासन स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय कर जल्द समस्या का समाधान करेगा और वर्षों से अधूरा पड़ा पीएचसी का सपना साकार होगा।

शिवसेना जिलाध्यक्ष को मिली जान से मारने की धमकी, एसएसपी से शिकायत, कार्रवाई की मांग

मूक-बधिर विद्यालय के संचालक पर गुंडे भेजने का आरोप



प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन सूरजपुर। शिवसेना ने विगत दिनों जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर विश्रामपुर स्थित ज्ञानोदय मूक-बधिर विद्यालय पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए जांच व कार्रवाई की मांग की थी। जिसपर प्रशासन की ओर से क्या कार्रवाई हो रही है यह तो अभी पता नहीं चल सका है। इस बीच एक और नया मामला सामने आया है जिसमें गुरुवार को शिवसेना ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर संचालक पर गुर्गे भेजकर शिवसेना के जिलाध्यक्ष को जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए

कार्रवाई की मांग की है। कार्रवाई के अभाव में आंदोलन की भी चेतावनी दी गई है। पुलिस अधीक्षक को सौंपे ज्ञापन में शिवसेना के जिलाध्यक्ष विष्णु वैष्णव द्वारा बताया गया है कि बुधवार 10 दिसंबर के दोपहर 12:30 बजे मानपुर के बैगापारा स्थित उनके घर पर दो अज्ञात लड़के बाईक से पहुंचे थे इस दौरान वे घर में नहीं थे उनकी अनुपस्थिति में घर पर मौजूद उनकी पत्नी को धमकाते हुए उन्होंने कहा कि विष्णु को समझा देना, बहुत नेतागिरी कर रहा है, उसे जान से उड़ा देंगे। तुम भी ज्यादा बोल रही हो, तुम्हें भी जान से खतर कर देंगे। हमें विजयराज अग्रवाल ने भेजा है। धमकी देने के बाद वे तुरंत बाईक स्टार्ट कर वहां से फरार हो गए। यह घटना न केवल मेरे व मेरे परिवार की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है, बल्कि यह स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि ज्ञानोदय मूक-बधिर विद्यालय मामले को उजागर करने पर मुझ पर दबाव बनाने और मुझे उद्वेग-धमकाने की साजिश रची जा रही है। शिवसेना जिलाध्यक्ष ने मामले की उच्चस्तरीय, निष्पक्ष एवं त्वरित जांच कराने एवं धमकी देने वाले व्यक्तियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी की मांग की है। उन्होंने कहा है कि ज्ञानोदय मूक-बधिर विद्यालय के संचालक विजयराज अग्रवाल को इस प्रकरण में मुख्य संज्ञाने मानते हुए मामले को संज्ञान लिया जाए तथा मेरे एवं मेरे परिवार के लिए सुरक्षा प्रदान की जाए। ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि यदि भविष्य में मेरे, मेरे परिवार अथवा शिवसेना कार्यकर्ताओं के साथ किसी भी प्रकार की अनहोनी, दुर्घटना या जानलेवा हमला होता है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी ज्ञानोदय कार्यकर्ताओं के साथ किसी भी प्रकार की अनहोनी, दुर्घटना या जानलेवा हमला होता है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी ज्ञानोदय मूक-बधिर विद्यालय के संचालक विजयराज अग्रवाल की होगी।

उक्त मामले को गंभीरता से लेते हुए संचालक एवं उनके गुण्डों के विरुद्ध तत्काल जांच कर अपराधिक मामला दर्ज करने की मांग की गई है। ज्ञापन में जिला प्रमुख कार्रवाई हेतु 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है और कार्रवाई के अभाव में शिवसेना संगठन द्वारा सम्भाग स्तर पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है। ज्ञापन सौंपने वालों में शिवसेना जिलाध्यक्ष विष्णु वैष्णव सहित महिला जिलाध्यक्ष पंकी पटेल, ग्रामीण जिला प्रमुख हेमंत महंत, जिला सचिव डॉ.आर एस ,नगर प्रमुख साहिल, ब्लॉक प्रमुख मोहन सिंह टोका, जिला प्रवक्ता मनोश दिवेदी, गौतम कुमार, रजनी सिंह, कौशल्या राजवाड़े, बालकुंवर, कलावती, अनिता सहित अन्य शिवसैनिक शामिल रहे।

गहनता से करें ईपिक नम्बर का परीक्षण : जयवर्धन

एसआईआर पर सख्त कलेक्टर भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का अनुपालन कराने फील्ड पर निकले

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन सूरजपुर। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी एस.जयवर्धन एस.आई.आर. कार्यों की प्रगति का जायजा लेने के उद्देश्य से विगत दिवस विश्रामपुर पहुंचे थे। निरीक्षण के दौरान उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का अनुपालन करवाने हेतु उपस्थित संबंधितों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए कलेक्टर ने एसआईआर में अनकलेक्टरेबल एवं पलायित लोगों की संख्या व स्पष्ट आंकड़ों को लेकर उपस्थित संबंधित अधिकारियों से जानकारी ली। उन्होंने कहा कि निर्धारित समय-सीमा के भीतर कार्य पूर्ण करना सबकी प्राथमिकता हो। उन्होंने श्रेणी सी अंतर्गत स्थायी रूप से

स्थानांतरित, दीर्घकालीन अनुपस्थित तथा पहले से पंजीकृत व्यक्तियों की गलत प्रविष्टि तथा स्थानांतरित व पहले से पंजीकृत व्यक्तियों के ईपिक नम्बर का परीक्षण गहनता के करने के स्पष्ट निर्देश दिये। कलेक्टर ने स्पष्ट कहा कि स्थायी रूप से स्थानांतरित, मृत अथवा अनुपस्थित व्यक्तियों के नामों को हटाने और पहले से पंजीकृत प्रविष्टियों का

अत्यंत सावधानीपूर्वक पुनरीक्षण किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि लक्ष्य-आधारित कार्यवाही सुनिश्चित की जाए, जिससे पुनरीक्षण कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही न हो। इस दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी पुष्पेंद्र शर्मा, एसडीएम श्रीमती शिवानी जायसवाल सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। इसके अलावा एसआईआर के संबंध में नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती कुसुमलता रजवाड़े, एस डी एम शिवानी जायसवाल एवं तहसीलदार सूरजपुर द्वारा नगर पालिका सूरजपुर व अन्य जनप्रतिनिधियों तथा बीएलओ को उपस्थित में नगरपालिका अंतर्गत आने वाले मतदान केंद्रों में एसडी लिस्ट पर चर्चा की गई।



तूहर टोकन' सर्वर फेल, घंटों इंतजार के बाद भी नहीं कट पा रहा टोकन

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन सूरजपुर। जिले के चांदनी बिहारपुर पहाड़ी अंचल में धान खरीदी के लिए किसानों को जारी होने वाला 'तूहर टोकन' किसानों के लिए परेशानी का



दिखाकर प्रक्रिया बंद हो जाती है। किसान बताते हैं कि वे कई दिनों से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक टोकन नहीं निकल पाया है चांदनी-बिहारपुर क्षेत्र पहाड़ी इलाका होने के कारण यहां नेटवर्क की समस्या पहले से ही आम बात रहता है। कई बार ऐप खुलता भी नहीं और थोड़ी देर बाद कोटा कंलीट का संदेश हो गई है। कई किसान कहते हैं कि धान तैयार है, घर में जगह नहीं है, लेकिन टोकन नहीं मिलने से बेच नहीं पा रहे। इससे उनके मन में चिंता और नाराजगी दोनों बढ़ रही है। किसानों का स्पष्ट कहना है कि यदि प्रशासन को ऑनलाइन में समस्या आती है, तो धान खरीदी केंद्रों में ही टोकन वितरण की व्यवस्था शुरू की जाए। किसानों ने जिला प्रशासन और खाद्य विभाग से मांग की है कि टोकन सिस्टम में सुधार किया जाए, सर्वर की क्षमता बढ़ाई जाए और नेटवर्क कमजोर क्षेत्रों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाए, ताकि किसान समय पर धान बेच सकें।

गर्भवती महिलाओं के बेहतर इलाज हेतु करें हरसंभव कार्य : कलेक्टर

महिला एवं बाल विकास तथा स्वास्थ्य विभाग की हुई संयुक्त समीक्षा बैठक

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन सूरजपुर। गुरुवार को कलेक्टर एस जयवर्धन की अध्यक्षता एवं जिला पंचायत सीईओ विजेन्द्र सिंह पाटेल की उपस्थिति में महिला एवं बाल विकास तथा स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त मासिक समीक्षा बैठक जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित की गई। बैठक में मुख्य स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी, जिला आयुर्वेद अधिकारी एवं अन्य चिकित्सक तथा महिला एवं बाल विकास विभाग से चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर, सभी सीडीपीओ सुपरवाइजर एवं सभी वन स्टॉप सेंटर की प्रभारी सहित अन्य कर्मचारियों उपस्थित रही। इस दौरान मुख्य स्वास्थ्य विशेष रूप से जिले में प्रसव संबंधी मामलों की समीक्षा की और स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रसव के मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग गंभीरता से कार्य करें। गर्भवती महिलाओं के बेहतर से बेहतर इलाज के लिए हरसंभव

कार्य करें। सभी सुपरवाइजर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं मितांनियों को शत-प्रतिशत एएनसी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए ताकि गर्भवती महिलाओं को संपूर्ण स्वास्थ्य सुविधा का लाभ प्रदान किया जा

सके। साथ ही इस सम्बन्ध में लापरवाही करने वाले अधिकारी एवं कर्मचारियों पर सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर ने जिले के स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध सुविधाओं, चिकित्सकों एवं नर्सिंग स्टाफ की उपलब्धता और उनके उपस्थिति की विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने हाई रिस्क प्रेगनेंसी मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही पर सख्त से सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए। गर्भवती महिलाओं की नियमित

जांच, ब्लड प्रेशर और हीमोग्लोबिन टेस्ट को प्राथमिकता से करने के निर्देश दिए, ताकि महिलाएं की श्रेणी में आने से बच सकें। साथ ही कलेक्टर ने जिले में प्रसव संबंधी मामलों के लिए स्वास्थ्य विभाग और महिला

सभी स्वास्थ्य केंद्र हर समय स्वास्थ्य कर्मियों की उपलब्धता हो। आंगनबाड़ी केंद्रों का समय पर संचालन, बच्चों की उपस्थिति, पोषण कार्यक्रम का नियमित आयोजन तथा बच्चों और महिलाओं को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। बच्चों के टीकाकरण को समय पर सुनिश्चित करने तथा वजन उत्सव के माध्यम से बच्चों की पोषण स्थिति को गंभीरता से सुधारने पर जोर दिया गया। चिरायु योजना के अंतर्गत हृदय रोग से पीड़ित बच्चों के उपचार, सर्जरी और सत्य साई अस्पताल में चल रहे इलाज की समीक्षा की गई। साथ ही सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित बच्चों की स्थिति एवं उपचार पर जानकारी ली गई तथा जिले में लगातार सिकल सेल स्क्रीनिंग करने के निर्देश दिए गए। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना, वय वंदन कार्ड निर्माण, बाल विवाह रोकथाम कार्यक्रम, बाल विवाह मुक्त

चांदनी-बिहारपुर क्षेत्र के किसान परेशान

कारण बना हुआ है। क्षेत्र के किसान रोज सुबह 8 बजे से मोबाइल लेकर लाइन में खड़े हो जाते हैं, ताकि समय पर टोकन मिल सके, लेकिन सर्वर की लगातार समस्या के कारण घंटों इंतजार के बाद भी टोकन नहीं कट पा रहा है। किसानों का कहना है कि जैसे ही टोकन कटने की प्रक्रिया शुरू करते हैं, ऐप लगातार कृपया प्रतीक्षा करें सर्वर बिजी जैसे संदेश दिखाता रहता है। कई बार ऐप खुलता भी नहीं और थोड़ी देर बाद कोटा कंलीट का संदेश

लेकिन अब तक टोकन नहीं निकल पाया है चांदनी-बिहारपुर क्षेत्र पहाड़ी इलाका होने के कारण यहां नेटवर्क की समस्या पहले से ही आम बात रहता है। कई बार ऐप खुलता भी नहीं और थोड़ी देर बाद कोटा कंलीट का संदेश

कार्यालय संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक राजमाता श्रीमती देवेन्द्र कुमारी सिंहदेव शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध चिकित्सालय अम्बिकापुर, सरगुजा (छ.ग.)

क्रमांक/5922/स्टोर/2025 अम्बिकापुर, दिनांक 09.12.2025

ई-प्रोक्यूरमेंट सिस्टम निविदा आमंत्रण सूचना

राजमाता श्रीमती देवेन्द्र कुमारी सिंहदेव शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध चिकित्सालय अम्बिकापुर (छ.ग.) की ओर से इम्प्लॉट के निविदा हेतु फर्मा/अभिकरणों से राजमाता श्रीमती देवेन्द्र कुमारी सिंहदेव शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध चिकित्सालय अम्बिकापुर सरगुजा (छ.ग.) में इम्प्लॉट हेतु ऑनलाइन निविदा निम्नानुसार आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र एवं अन्य जानकारी हेतु वेबसाइट <https://eproc.cgstate.gov.in> में देखा जा सकता है।

क्र.	निविदा का नाम	सीजी ई प्रोक्वो निविदा क्रमांक	ऑनलाइन जमा करने की प्रारंभिक तिथि एवं समय	ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	भौतिक रूप से जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	निविदा खुलने की तिथि एवं समय
1	इम्प्लॉट	181427	15.12.24.25 10:00 AM	05.01.2026 02:00 PM	05.01.2026 03:00 PM	05.01.2026 04:00 PM

स्थान :- कार्यालय, संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक राजमाता श्रीमती देवेन्द्र कुमारी सिंहदेव शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध चिकित्सालय, अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.)

संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक राजमाता श्रीमती देवेन्द्र कुमारी सिंहदेव, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध चिकित्सालय, अम्बिकापुर सरगुजा (छ.ग.)

जी-252605354 / 1

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर मंडल

अनुलग्नक-अ

कार्य का विवरण - बिलासपुर मंडल एसईसी रेलवे के अधिकार (ABKP) रेलवे स्टेशन में पे एंड यूज शौचालय के संचालन और प्रबंधन के लिये लाइसेंसधारी की लागत पर लाइसेंस आबंटन हेतु ई-नीलामी आमंत्रित की गई है।

पंच (05) वर्षों की अवधि के लिये बिलासपुर मंडल एसईसी रेलवे के अधिकार (ABKP) रेलवे स्टेशन में पे एंड यूज शौचालय के संचालन और प्रबंधन के लिये लाइसेंसधारी की लागत पर लाइसेंस आबंटन हेतु ई-नीलामी आमंत्रित की गई है। कोटेशन पहले ही IREPS वेबसाइट (<https://ireps.gov.in>) पर दिनांक 04.12.2025 को प्रकाशित की जा चुकी है। विवरण निम्नानुसार है:-

कोटेशन क्र.	श्रेणी	नैतिक बंधन	लॉट क्रमांक	लॉट विवरण	अनुबंध अवधि
PnU-TOI-ABKP-26	Pay & Use Toilets	19-12-25 13:00:00	PnU-BSP-ABKP-TOI-19-25-2	बिलासपुर मंडल एसईसी रेलवे के अधिकार (ABKP) रेलवे स्टेशन में पे एंड यूज शौचालय के संचालन और प्रबंधन के लिये लाइसेंसधारी की लागत पर लाइसेंस आबंटन हेतु ई-नीलामी आमंत्रित की गई है।	1826 दिन

सोपीआर/10/FL/527 सहायक वाणिज्य प्रबंधक (मालमाझ-1), द.पू.म. रेलवे, बिलासपुर

South East Central Railway @secrail

समाजिक सद्भाव बिगाड़ने वाले स्वा. कर्म. पर कार्रवाई की मांग

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन सूरजपुर। गौसिया मुस्लिम कमेटी ने आज एसपी को एक ज्ञापन देकर समाजिक सद्भाव

में मुस्लिम समुदाय के भावनाओं को आहत करने वाला पोस्ट ने कहा है कि पोस्ट डालने वाले सर्वधर्म युवक पर फौरन कानूनी कार्रवाई की जाए अन्यथा समाज उग्र

आंदोलन करने को विवश होगा। इस पोस्ट पर मुस्लिम कमेटी विशुनपुर व कैलाशपुर ने भी आपत्ति दर्ज कराई है।



बिगाड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मचारी पर कार्रवाई की मांग की है। गौसिया मुस्लिम जिला कमेटी ने दिए ज्ञापन में बताया है कि रामनिवास साहू नामक युवक जो स्वास्थ्य कर्मी है, के द्वारा वाट्सएप के ऑफिसियल रूप

डाला गया है। जिससे समाज में रोष की स्थिति है ज्ञापन में कहा गया है कि उक्त पोस्ट भड़काऊ तथा सामाजिक सद्भावना को

संपर्क करें
समाचार, ईशतहार, विज्ञापन
हेतु संपर्क करें।
दैनिक छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन
गौरव पथ, गुरुद्वारा के पास बाबूपारा
अम्बिकापुर
मो. 7566950555
9713108088

सरगुजा फ्रंटलाइन

पूँजीपतियों के इशारे पर जल, जंगल और जमीन को लूट रही सरकार-जरिता लैतफलांग

सत्ता परिवर्तन के बाद खनिजों के खनन को लेकर बनी गंभीर टकराव की स्थिति

छ.ग.फ्रंटलाइन अम्बिकापुर। कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव जरिता लैतफलांग ने गुरुवार को मैनपाट का दौरा करके बॉक्साइट खनन के प्रभावितों से मुलाकात किया। हाल ही में बॉक्साइट खदानों के लिए बिना किसी पूर्व सूचना के पर्यावरण स्वीकृति के लिए आयोजित सभा में स्थानीय निवासियों और प्रशासन के बीच संघर्ष की स्थिति निर्मित हो गई थी। राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद छत्तीसगढ़ के उत्तरी जिलों में खनिजों के खनन को लेकर गंभीर टकराव की स्थिति बनी हुई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व को नजर इन पर बनी हुई है। इसका अंदाजा कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव जरिता लैतफलांग का हालिया दौरा ऐसे ही क्षेत्रों पर केंद्रित रहने से लगता है।



पारसोढ़ीकला, फिर मैनपाट के दौर के बाद उन्होंने कहा कि लगभग सभी जगहों पर यह स्पष्ट हुआ है कि स्थानीय निवासियों की मंशा और स्वीकृति के विपरीत खनन कंपनियों के मुनाफे के लिए सरकार अपने तंत्र का इस्तेमाल कर उन्हें बेदखल कर रही है। प्रभावित लोगों से मुलाकात के दौरान उनकी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरगुजा में पांचवीं अनुसूची लागू है, ताकि यहां के जल, जंगल, जमीन पर इनका अधिकार कायम रहे। इधर छत्तीसगढ़ की मौजूदा भाजपा सरकार पूँजीपतियों के इशारे पर आपके इस जल, जंगल और जमीन को लूट रही है। इस लूट के बाद पांचवीं अनुसूची से आपके मिले अधिकार बेमानी हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि जल, जंगल, जमीन की लड़ाई में कांग्रेस आपके साथ है। कांग्रेस विधानसभा के

लोकतांत्रिक संघर्ष का हिड़मा बनुंगा

30 दिसंबर की जनसुनवाई में एक आक्रोशित युवक ने मोडिया को यह कहकर सनसनी फैला दी थी कि ऐसी ही वजहों से लोग हिड़मा बनते हैं। फूलचंद मांझी नाम का यह युवक आज की मुलाकात के दौरान मौजूद था। बीएससी द्वितीय वर्ष के इस छात्र ने कहा कि हिड़मा बोलने का यह आशय नहीं है कि हथियार उठाना चाहता हूं। मैं अपने आदिवासी समाज के हक की लोकतांत्रिक लड़ाई लड़ना चाहता हूं। उसने कहा कि खनन के काम में स्थानीय लोगों के लिए कोई रोजगार नहीं है। बॉक्साइट निकलने के बाद खनन कंपनियां भूखंडों को जस का तस छोड़ देती हैं। इसमें गिरने से मवेशियों के साथ ही स्थानीय निवासियों की मौत हो रही है।

शीतकालीन सत्र में इन मुद्दों को जोर-शोर के साथ उठाने की तैयारी कर रही है। सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस जिलाध्यक्ष बालकृष्ण पाठक ने कहा छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके आदिवासी समुदाय के हित में खड़े रहने की संभावना थी, लेकिन पूँजीपतियों और कंपनियों के द्वारा आदिवासियों के जल, जंगल, जमीन को बेखौफ होकर लूटा जा रहा है। इस दौरान जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष मो. इस्लाम, डॉ. लालचंद यादव, अनिल सिंह, बलराम यादव, तिलक बेहरा, अटल यादव, फूलसाय लकड़, राजेश गुप्ता, संतोष गुप्ता, गणेश सोनी, बदरुद्दीन इराकी, अमित सिंह सहित मैनपाट ब्लॉक कांग्रेस के पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष एवं कार्यकर्ता मौजूद थे।

संत हरकेवल शिक्षा महाविद्यालय में विश्व मानवाधिकार दिवस पर चर्चा

छ.ग.फ्रंटलाइन अम्बिकापुर। संत हरकेवल शिक्षा महाविद्यालय में आईक्यूएसी एवं सामाजिक विज्ञान क्लब के संयुक्त तत्वाधान में विश्व मानव अधिकार दिवस मनाया गया, जिसमें जेंडर इक्वलिटी पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राजेश सिंह सिसोदिया ने पांच सत्याग्रह, विशिष्ट अतिथि सुखूषू दास गांधी फेलो, अंशु पाण्डेय उपस्थित रहें। राजेश सिंह सिसोदिया ने शिक्षार्थियों को संबोधित करते हुए बताया कि विश्व मानव अधिकार दिवस हर वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन वर्ष 1948 में मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को संयुक्त राष्ट्र द्वारा आधिकारिक रूप से स्वीकार किया गया था। घोषणा को पारित करने में एलेनोर रूजवेल्ट की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार



आयोग की अध्यक्ष के रूप में इसे आकार देने में अहम योगदान दिया। कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों ने विद्यार्थियों को बताया कि जेंडर इक्वलिटी का अर्थ केवल महिला-पुरुष समानता नहीं है, बल्कि यह समाज में हर व्यक्ति को चाहे उसका लिंग, जाति, धर्म, भाषा या सामाजिक स्थिति कुछ भी हो समान अवसर व सम्मान देने की व्यवस्था है। प्राचार्य डॉ. अंजन सिंह ने कहा कि मानवाधिकार और जेंडर इक्वलिटी जैसे विषय केवल पढ़ने लिखने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इन्हें जीवन में आत्मसात करना आवश्यक है। शिक्षा का समापन वास्तविक उद्देश्य व्यक्ति के भीतर

संवेदनशीलता, समानता, सम्मान और नैतिक मूल्यों को विकसित करना है। प्रत्येक शिक्षार्थियों को समाज में जागरूकता फैलाने, भेदभाव समाप्त करने और एक न्यायपूर्ण वातावरण बनाने में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। अंत में डॉ. रानी पाण्डेय ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने मानवाधिकार एवं जेंडर इक्वलिटी के मूल सार को स्पष्ट करते हुए कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के समान अधिकार, समान सम्मान तथा स्वतंत्रता मिलना चाहिए। समाज तभी प्रगतिशील बन सकता है जब हम लैंगिक समानता को अपने आचरण और व्यवहार में अपनाएं। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ।

विद्यार्थियों ने कानूनी प्रावधानों को जाना, किए सवाल

कला केंद्र मैदान में नए कानून की जानकारी हेतु लगाई गई प्रदर्शनी

छ.ग.फ्रंटलाइन अम्बिकापुर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में स्थानीय कला केंद्र मैदान में नए कानून की जानकारी हेतु प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी का अवलोकन करने 10 दिसम्बर को संत हरकेवल महाविद्यालय के बीएड प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के छात्र-छात्राओं का आना हुआ, जिसमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं नगर पुलिस अधीक्षक ने भारतीय न्याय संहिता, भारतीय सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, साइबर अपराध एवं यातायात के संबंध में विस्तार पूर्वक बताया। प्रदर्शनी में महाविद्यालय के छात्रों को संबोधित करते हुए नगर पुलिस अधीक्षक राहुल बंसल ने बताया कि किस प्रकार भारतीय न्याय संहिता,



भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में निहित कानून द्वारा हमारी न्याय प्रणाली को अधिक आधुनिक पारदर्शी एवं नागरिकों के हित में बनाया गया है। उन्होंने डिजिटल अपराध अंतर्गत वित्तीय धोखाधड़ी, सोशल मीडिया अपराध, फर्जी अकाउंट, डेटा चोरी जैसे अपराधों में प्रभावी कार्रवाई हेतु नए कानून की आवश्यकता एवं विशेषता पर जानकारी दी।

ग्राहक बनकर पहुंचे दो युवक, इधर जेवरातों से भरा पेटी हुआ गायब

छ.ग.फ्रंटलाइन अम्बिकापुर। सरगुजा जिले के मैनपाट, कमलेश्वरपुर थाना अंतर्गत साप्ताहिक बाजार से व्यवसायी का ज्वेलरी से भरा पेटी अज्ञात लोगों ने चोरी कर लिया। चोरी गए जेवरों की कीमत लगभग दो लाख रुपये है। जानकारी के मुताबिक सीतापुर निवासी बदननाथ सोनी पिता स्व. जानकी राम सोनी 68 वर्ष, आठ दिसम्बर को रोपाखार में लगने वाले साप्ताहिक बाजार में दुकान का संचालन कर रहे थे। शाम करीब 5.15 बजे वे दुकान बंद करने के लिए एक पेटी में ज्वेलरी समेत करके रख रहे थे। इसी बीच दो लोग ग्राहक बनकर आए, जिन्हें थोड़ा अंधेरा होने के कारण वे अपने मोबाइल का टॉच जलाकर ज्वेलरी दिखाने लगे। इस दौरान पीछे और दूसरे दुकान के पास खड़े सदिग्ध व्यक्ति को ग्राहकों को सामान दिखाने के चक्कर में उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। इसी बीच पीछे से सोने-चांदी की ज्वेलरी का पेटी चोरी करके कोई भाग गया। ज्वेलरी व्यवसायी ने संभावना व्यक्त की है, ग्राहक बनकर आए युवकों का ही साथी उनके पीछे खड़ा था, जो उनकी व्यस्तता को देखते हुए जेवर से भरा पेटी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया। इधर ग्राहक बनकर पहुंचे दोनों व्यक्ति भी सामान पसंद नहीं आने की बात कहते हुए थोड़ी दूर खड़ी मोटरसाइकल से चले गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

पेटी में सहेजकर रखा था लाखों का सामान
व्यवसायी ने पुलिस को दिए लिखित शिकायत पत्र में कहा कि पेटी में चांदी के जेवरों में 25 जोड़ी पायल, 20 नग चैन, 15 नग बच्चों को पहनाने वाला बेरा, 04 नग मंगलसूत्र, 30 नग चन्द्रमा, 25 नग लोकेट, 30 नग अंगुठी, 75 ग्राम चांदी का ताबीज, 100 ग्राम टप्प एवं बाली, 100 ग्राम बिछिया, सोने के जेवरों में 02 जोड़ी टप, 03 जोड़ी लटकन, 04 लोकेट, 01 कुण्ड, 03 मोती दाना, 07 नथिया, 05 ग्राम नोज पिन, 04 डब्बा सोना पॉलिस किया हुआ कौल, 02 कम्प्यूटर कांटा, उधारी खाता, बिल बुक रखा था। व्यवसायी ने अन्य लोगों के साथ मिलकर जेवरों की पेटी को तलाशने का प्रयास किया, लेकिन पता नहीं चला।

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री ने किया स्कूल भवन का भूमि पूजन

छ.ग.फ्रंटलाइन अम्बिकापुर। प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने सरगुजा जिले के अम्बिकापुर विकासखण्ड स्थित ग्राम पंचायत बिनकरा में सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल भवन के निर्माण का भूमि पूजन किया। बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने और उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए मंत्री ने विधायक निधि से 20 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की है। इस अवसर पर बिनकरा गांव के पसिंदर राजवाड़े और उनके परिवार ने शिक्षा के क्षेत्र में योगदान देते हुए लगभग 50 डिस्मिल भूमि दान कर गांव वालों के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत किया। यह दान गांव की शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा देगा। मंत्री राजेश अग्रवाल ने अपने उद्घोष में कहा कि शिक्षा ही समाज की असली ताकत है। बिनकरा के बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए इस नए स्कूल भवन का निर्माण आवश्यक था। भूमि दान करने वाले परिवार और गांव के सभी लोगों को उन्होंने दिल से धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा हमारा उद्देश्य प्रदेश के हर बच्चे के लिए आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है, इस दिशा में हम निरंतर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि शिक्षा से ही व्यक्ति और समाज का विकास संभव है। बिनकरा गांव में सरस्वती शिशु मंदिर के नए स्कूल भवन का निर्माण न केवल इस गांव के बच्चों के लिए बल्कि पूरे क्षेत्र के भविष्य के लिए एक मजबूत आधारशिला साबित होगा। उन्होंने अपेक्षा व्यक्त की, यह प्रयास शिक्षा के क्षेत्र में नई उपलब्धियां और उज्ज्वल भविष्य लेकर आएगा। स्थानीय परिवार द्वारा भूमि दान जैसा कदम समाज में एकता और विकास की मिशाल है। हमारा संकल्प है कि प्रदेश के हर बच्चे तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचे जिससे कि वे अपने सपनों को पूरा कर सकें।

मानव अधिकार दिवस पर बीएड के विद्यार्थियों ने बनाई मानव श्रृंखला

छ.ग.फ्रंटलाइन अम्बिकापुर। सरस्वती शिक्षा महाविद्यालय सुभाषनगर में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई ने मानव अधिकार दिवस का आयोजन किया। इस दौरान बी.एड. प्रथम वर्ष के प्रशिक्षणार्थियों ने प्रेरणादायक मानव श्रृंखला बनाकर सामाजिक एकता, जागरूकता, सहयोग की भावना एवं सामुदायिक दायित्व को बढ़ावा देने का संदेश दिया। मानव श्रृंखला के माध्यम से प्रशिक्षणार्थियों ने संदेश दिया कि समाज में किसी भी सकारात्मक परिवर्तन के लिए सामूहिक प्रयास ही सबसे अधिक प्रभावी हैं। प्रशिक्षणार्थियों ने न केवल अनुशासन और टीम वर्क का परिचय दिया, बल्कि यह भी सिद्ध किया कि शिक्षक बनने की प्रक्रिया में सामाजिक उत्तरदायित्व को समझना और उसे व्यवहार में लाना कितना आवश्यक है। इस दौरान महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. श्रद्धा मिश्रा, कार्यक्रम अधिकारी रासेयो रानी रजक, रेड रिबन क्लब प्रभारी सविता यादव, सहायक प्राध्यापक उर्मिला यादव, मिथलेश कुमार गुर्जर, सुप्रिया सिंह, सीमा बंजारे, पूजा रानी, ज्योत्सना राजभर, अर्चना सोनवानी, गोल्डन सिंह एवं बीएड के प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति रही।

बीमार युवक की मौत, पुलिस ने कराया पोस्टमार्टम

छ.ग.फ्रंटलाइन अम्बिकापुर। लुंडा थाना क्षेत्र के ग्राम डडगांव निवासी युवक की अस्पताल लाते तक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सोनू नागेश पिता केंदल नागेश पीलिया की बीमारी से पीड़ित था। तबियत खराब होने पर बुधवार को स्वजन उसे होली क्रॉस अस्पताल अम्बिकापुर लेकर पहुंचे, यहां जांच के बाद चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। संदेह निवारण के लिए अस्पताल से मिली सूचना पर पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराया है। मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है। पत्थर से हमला के बाद मचान को किया आग के हवाले, ग्रामीणों की बची जान

छ.ग.फ्रंटलाइन अम्बिकापुर। बलरामपुर जिला के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र में पैरा डालकर मचान बना रहे ग्रामीणों पर गांव के ही लोगों ने पत्थर से वार करके मचान में आग लगा दिया। मामले में शंकरगढ़ थाना पुलिस ने आठ लोगों के विरुद्ध बलवा सहित अन्य गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। थाना क्षेत्र के ग्राम लहसुनपाट निवासी रामक्यास पिता साधुचरण यादव 37 वर्ष ने पुलिस को बताया है कि 09 दिसम्बर को सुबह वह गांव के किनेश्वर यादव, जमुना यादव के साथ मिलकर स्वयं के मचान में पैरा चढ़ा रहा था। करीब 11.30 बजे रामलाल यादव, दिलीप यादव, नागेन्द्र यादव, जयप्रकाश यादव, उपेन्द्र यादव, अरविन्द यादव, कुवला यादव, हीरामनी यादव मौके पर पहुंचे और हमारे जमीन में क्यों मचान बनाकर पैरा चढ़ा रहे हो, कहते हुए गाली-गलौज करने लगे और जान से मारने की धमकी देते हुए रामलाल यादव, नागेन्द्र यादव पत्थर चलाने लगे। रामक्यास की पत्नि सम्पतिया इन्हें समझादस देते हुए पत्थर चलाने से मना की तो आरोपी उसके साथ भी गाली-गलौज, मारपीट करने लगे।

जिला पंचायत सदस्य ने धान खरीदी केंद्र व छात्रावासों का किया निरीक्षण

छ.ग.फ्रंटलाइन उदयपुर। भाजपा नेत्री जिला पंचायत सदस्य राधा रवि आए दिन किसानों एवं ग्रामीणों की समस्याओं से रूबरू होकर उसका निपटारा करने की कोशिश में लगे रहती हैं, जिससे क्षेत्र की जनता का विश्वास उनके प्रति बढ़ रहा है। बोते बुधवार को क्षेत्र का दौरा करते हुए वे धान खरीदी केंद्र ग्राम रिखी पहुंचीं और क्षेत्र के किसानों को धान बेचने में किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो इन्हें देखते हुए एग्रीस्टेक, टोकन और हमाली जैसी समस्याओं को सुनकर इसका त्वरित निराकरण करने समस्त समिति प्रबंधकों को निर्देशित किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्कूलों और छात्रावासों का भी सघन दौरा किया। छात्रावास में पढ़ने वाले बच्चों से खान-पान, रहन-सहन पर सीधा संवाद किया और उनका हाल-चाल जाना। छात्रावास अधीक्षकों से मुलाकात करके बच्चों को ठंड में किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसके लिए पर्याप्त गर्म कपड़ों की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। इस दौरान भाजयुमो महामंत्री नवीन कुमार महंत, सदस्य संदीप कुमार और ग्रामीण मौजूद रहे।



भाजपा जिला अध्यक्ष ने किसानों से किया सीधा संवाद

छ.ग.फ्रंटलाइन लखनपुर। भाजपा मंडल लखनपुर के नेतृत्व में गुरुवार को लखनपुर धान खरीदी केंद्र



का निरीक्षण करके भाजपा जिला अध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने उपस्थित किसानों से सीधे संवाद किया। निरीक्षण के दौरान जिला अध्यक्ष ने किसानों को आश्वस्त किया कि उनके धान का एक-एक दाना सरकार खरीदेगी। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साव की सुशासन नीति है। किसानों को चिंता करने या परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सिसोदिया ने किसानों को बताया कि सभी समितियों में भाजपा निगरानी समिति का गठन किया गया है। किसानों को सुविधा, मार्गदर्शन और सही जानकारी प्रदान करने के लिए धान खरीदी केंद्रों पर हेल्प डेस्क स्थापित किए गए हैं। इन हेल्प डेस्क पर किसानों की शिकायतें एवं समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाएगा। मंडल अध्यक्ष दिनेश बारी, भाजपा जिला उपाध्यक्ष दिनेश साहू, ओबीसी मोर्चा जिला अध्यक्ष राजेंद्र जायसवाल ने भाजपा सरकार की किसान हितैषी नीतियों, पारदर्शी धान खरीदी व्यवस्था और प्रशासनिक सहयोग पर प्रकाश डाला। अंत में जनपद उपाध्यक्ष कामेश्वर राजवाड़े ने आभार प्रदर्शन करके भाजपा नेतृत्व को किसानों के प्रति संवेदनशीलता के लिए धन्यवाद दिया। इस दौरान मुख्य रूप से पूर्व मंडल अध्यक्ष सुभाष अग्रवाल, युजकिशोर पांडे, समिति अध्यक्ष बोधन सिंह, मंडल उपाध्यक्ष यतेंद्र पांडे, अमित गुप्ता, सत्यनारायण साहू, महामंत्री सचिन अग्रवाल, महेश्वर राजवाड़े, सुरेश जायसवाल, राकेश साहू, घरभरन राजवाड़े, सत्यनारायण तिवारी, काशी साहू, रंजीत दास सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और किसान मौजूद रहे।

नशीली इंजेक्शन की तस्करी करते बंटी-बबली गिरफ्तार



छ.ग.फ्रंटलाइन भगतवा। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर नशीली इंजेक्शन की अवैध बिक्री करने वाले दिनेश राव उर्फ बबली और सोनिया उर्फ बंटी, द्वय निवासी शिवनंदनपुर विश्रामपुर को गिरफ्तार किया है। इनके विरुद्ध धारा 21(सी) एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। कार्रवाई दौरान आरोपी दिनेश राव उर्फ बबली के कब्जे से 150 नग एक्विल इंजेक्शन, 150 नग रिक्सोजेसिक इंजेक्शन, परिवहन में प्रयुक्त स्क्वी एक्टवा क्रमांक सीजी 15 डीटी 5304 और दो मोबाइल फोन जब्त किया। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके रिमांड पर न्यायालय में पेश किया गया। कार्रवाई में चौकी बसदई प्रभारी योगेंद्र जायसवाल, प्रधान आरक्षक शिवकुमार सारथी, आरक्षक आदित्य कुमार यादव, राकेश सिंह, अशोक केवट, देवदत्त दुबे, सैनिक अनिल विश्वकर्मा, महिला आरक्षक पूनम सिंह और प्रफुल्ल मिश्र की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस ने बताया इसी प्रकरण से जुड़े आरोपियों राही खान निवासी सिरसी, जमडौ निवासी पवन पाटिल, सरवन कुमार और मोहर मनिया को पहले ही उन्होंने जेल भेज दिया है।

शासकीय एवं गैर शासकीय बैंकों के सुरक्षा जांच में जुटी पुलिस

छ.ग.फ्रंटलाइन अम्बिकापुर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश अग्रवाल ने राज्यपत्रित अधिकारियों सहित सभी थाना चौकी के प्रभारियों को सुरक्षित बैंकिंग, अपराधिक गतिविधियों में कमी लाने एवं आम जनता की सुरक्षा दृष्टि से शासकीय एवं गैर शासकीय बैंकों के सुरक्षा जांच के निर्देश दिए हैं। इसी तारतम्य में 10 दिसम्बर को पुलिस ने बैंकों में लगे सीसीटीवी कैमरे की स्थिति, सुरक्षा गार्ड, मुख्य द्वार की मजबूती, बैंकों में सायरन, आपातकाल हेतु उपलब्ध संपर्क नंबर, सुरक्षा कर्मियों के पास उपलब्ध हथियार एवं उसकी स्थिति, कार्टूसों की संख्या, बैंकों में कार्यरत नियमित एवं अनियमित कर्मचारियों का सत्यापन इत्यादि बिंदुओं पर जांच करके रिपोर्ट प्राप्त की। शाखा प्रबंधकों से बैंकों में संदिग्ध व्यक्तियों एवं गतिविधियां सामने आने पर इसकी सूचना नजदीकी थाना अथवा पुलिस कंट्रोल रूम में देने हेतु निर्देशित किया गया।